

दैनिक

मीडिया ऑडिटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

: वीपी बॉक्स :

नॉटो समिट में ट्रम्प बोले-
ईरान से सीज़फायर खत्म

खतरनाक लोगों को निशाना बनाया; अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमले किए



तेहरान ,एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हुआ समझौता (MoU) अब खत्म हो चुका है। उन्होंने यह बयान तुर्किये के अंकारा में NATO शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया।

ट्रम्प ने कहा, 'हमने बीती रात बेहद ताकतवर हमला किया। हमने ईरान के बेहद खतरनाक लोगों को निशाना बनाया।' उन्होंने ईरानी लीडरशिप पर कहा, 'वे बीमार हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है।'

इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया था कि उसने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। कार्रवाई में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस (IRGC) की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया।

गैंगस्टर तॉर्सेस पर अमेरिका में
हत्या का केस, चार्जशीट दायर

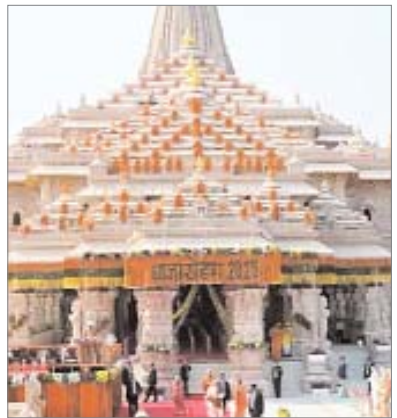
गोल्डी बराड़ पर 50 हजार डॉलर इनाम; दावा- दोनों ने कनाडा में निज्जर की हत्या कराई



जालंधर,एजेंसी। भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ अमेरिका में हत्या समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका अब भारत से इन दोनों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा।

अमेरिकी अधिकारियों ने यह बात अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भारत से जुड़े इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई के बाद कही। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कनाडा की एजेंसियों के साथ मिलकर 7 देशों में ऑपरेशन हाई बॉल चलाया और 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 37 लोगों के खिलाफ अमेरिकी फेडरल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

चार्जशीट में लॉरेंस बिस्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा समेत अन्य आरोपियों पर 2023 में कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आरोप सही साबित हुए तो इन्हें 10 साल से अधिक जेल हो सकती है।



अयोध्या,एजेंसी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस टीम बुधवार सुबह 7:36 बजे फैजाबाद जेल पहुंची और तीन आरोपियों को पुलिस लाइन

मुंबई एयरपोर्ट में रनवे पर आमने-सामने आए प्लेन

एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद खड़ा था, एअर इंडिया प्लेन ने टेक-ऑफ रन शुरू

मुंबई,एजेंसी। मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार रात को हादसा टल गया। एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमान एक ही रनवे पर आमने-सामने आ गए। घटना रात 10 बजे की बताई गई है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, एअर इंडिया के विमान ने एयर ट्रेफिक कंट्रोलर के निर्देश पर टेक-ऑफ रन रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद रनवे से हटा नहीं था, तभी दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया का विमान उसी रनवे से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था।

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि सिलिगुड़ी से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रनवे खाली कर ही रही थी। जबकि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट

सूरत में बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 36 घंटे में 18 इंच बारिश



राममंदिर चढ़ावा चोरी-एसआईटी को ट्रस्ट की फर्जी चंदा रसीदें मिलीं

● 3 आरोपियों से पूछताछ जारी ● पुलिस सर्राफा कारोबारी के यहां भी पहुंची

लेकर गई। SIT रिपोर्ट के अनुसार, तीनों आरोपी CCTV फुटेज में नोटों को जेब में रखते हुए नजर आए थे। इस बीच, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि चंपत राय से मिलने पहुंचे हैं। चंपत राय राम मंदिर के निकट रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम में एकांतवास कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने लेटर जारी कर चुपी तोड़ी थी।

कहा था- मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। इधर, SIT ने अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े आयोजनों के खर्च की जांच शुरू कर दी है। SIT 22 जनवरी 2024 के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह और 25 नवंबर 2025 के

ध्वजारोहण के बिल और वाउचर खंगाल रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक, प्राण-प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें 8 हजार मेहमान आए थे। ध्वजारोहण पर 10.12 करोड़ खर्च हुए।

जबकि अयोध्या पुलिस ने मिल्कीपुर क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा के साथ इनायतनगर के एक सर्राफा कारोबारी और एक बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी के यहां भी दबिश दी। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी द्वारा खरीदी गई संपत्ति या सामान के भुगतान का तरीका (पैमेंट मोड) क्या था।

बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद: सरपेंड निजी सचिव पर एफआईआर

» सीएम बोले- यह मां-बाप की हत्या जैसा महापाप; जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनी

चमोली ,एजेंसी। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित हेरफेर मामले में पहली बड़ी आपराधिक कार्रवाई हुई है। मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान की तहरीर पर निर्लांबित निजी सचिव प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बद्रीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 और 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए हाई

इस दौरान सीएम ने कहा... ये गौहत्या जैसा पाप है। जो लोग ऐसे पवित्र स्थानों पर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उनका अपराध वैसा ही है जैसे कोई अपने मां-बाप की हत्या कर दे। यह महापाप है। यह अक्षम्य अपराध है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लेवल कमेटी गठित की। जिसे 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच, चढ़ावा विवाद उजागर करने वाले काल भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री को बुधवार को पुलिस ने देहरादून स्थित उनके कार्यालय में करीब छह घंटे तक नजरबंद रखा। खत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे।

मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे

» बोले- हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला; हजार साल पुराना मंदिर, दीवारों पर रामायण की कहानी

जकार्ता,एजेंसी। पीएम मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योगयाकार्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। दोनों ने मंदिर के संरक्षण-जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मंदिर में दर्शन भी किए।

उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा- मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है।



सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौर का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम आज शाम इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न रवाना होंगे। उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा 8 से 10 जुलाई तक है।

प्रम्बानन मंदिर एक हजार साल पुराना, दीवारों पर रामायण लिखी... इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योगयाकार्ता के पास स्थित प्रम्बानन मंदिर दक्षिण-पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहले स्थान पर कंबोडिया का अंगकोर वाट है। प्रम्बानन मंदिर एक हजार साल पुराना है।

बंगाल में बच्ची से रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

● पुलिस बोली- राइफल छीनकर भाग रहा था ● तालाब से मिला था नाबालिग का शव

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर का एक आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था।

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच



मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर

दिया। बारुईपुर में 12 साल की लड़की 4 जुलाई को लापता हो गई थी। 5 जुलाई को उसका शव एक तालाब से मिला। पोस्टमॉर्टम में रेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने रेप-मर्डर के आरोप में प्रभास सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दूसरा आरोपी आनंद सरदार है।

लड़की के सिर पर या तो किसी भारी चीज से वार किया गया था या उसे किसी सख्त सतह पर पटका गया था। शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर खरोंच

आरोपियों ने बच्ची को जिंदा तालाब में फेंका था... पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की, जिसमें चार लोग लड़की को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने बताया कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम में लड़की के सिर और प्राइवेट पार्ट्स पर घोट के निशान मिले।

और काटने के निशान थे। उसके फेफड़े और पेट में पानी मिला। आरोपियों ने उसे जिंदा ही तालाब में फेंक दिया था। डूबने और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई।

भारत से कैलाश पर्वत दर्शन के लिए करना होगा इंतजार

» व्यू पॉइंट पर हर दिन बदलता रहता है मौसम

पिथौरागढ़, एजें सी। तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के भारत से दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अभी करीब दो महीने और इंतजार करना होगा। फिलहाल इनर लाइन परमिट (ILP) जारी नहीं किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सितंबर के आसपास परमिट शुरू होने पर आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले श्रद्धालु 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपुलेख (ओल्ड लिपुवास) जाकर भारत की सीमा से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। इस वर्ष यात्रा सीजन की शुरुआत में बड़ी

2 माह बाद जारी होंगे परमिट



संख्या में श्रद्धालु ओल्ड लिपुलेख पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। बाद में खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से सेना ने इस क्षेत्र में आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी थी। प्रशासन और सेना के बीच वार्ता के बाद सीमित संख्या में पर्यटकों को

घना कोहरा छने पर कैलाश पर्वत दिखाई नहीं देता। ओल्ड लिपुलेख तक सड़क बन चुकी है, लेकिन अंतिम चोटी तक पहुंचने के लिए करीब 300 मीटर पैदल खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। कई बार ऑक्सिजन की कमी और कठिन चढ़ाई के कारण वाहन बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, जिससे यात्रियों को करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

सभी श्रद्धालुओं को अनुमति देने की मांग: स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और सेना समन्वय बनाकर सभी यात्र श्रद्धालुओं को ओल्ड लिपुलेख तक जाने की अनुमति दे, ताकि सीमांत क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। पिछले वर्ष आदि

इसलिए अहम है यह व्यू पॉइंट... ओल्ड लिपुलेख का यह व्यू पॉइंट इसलिए खास माना जा रहा है, क्योंकि यहां से श्रद्धालु भारत की सीमा के भीतर रहकर ही तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और जैन, बौद्ध तथा बोन धर्म में भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है।

कैलाश और ओम पर्वत आने वाले यात्रियों के लिए ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन की व्यवस्था शुरू की गई थी। तब करीब 10 हजार श्रद्धालुओं ने इसका लाभ उठाया था। डीएम आशीष भट्टाई ने बताया कि सेना से समन्वय के बाद श्रद्धालुओं को कैलाश दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल इनर लाइन परमिट जारी नहीं हो रहे हैं। परमिट शुरू होने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत आने वाले श्रद्धालु

ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। पारंपरिक कैलाश-मानसरोवर यात्रा में श्रद्धालुओं को तिब्बत जाकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा और मानसरोवर झील के दर्शन करने पड़ते हैं। इसके लिए पासपोर्ट, वीजा और लंबी तथा महंगी यात्रा की जरूरत होती है। हालांकि, ओल्ड लिपुलेख से केवल कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं और श्रद्धालु मानसरोवर झील तक नहीं पहुंचते।

इंतजाम भी किया। सुरक्षाबल पिछले कई दिनों से गांवों और आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। अक्टूबर 2025 में NIA कोर्ट ने इनके खिलाफ नोटिस जारी किया था और हाल ही में उनका नाम अप्रैल 2026 के पहलगांव आतंकी हमले की जांच से भी जुड़ा था। पहलगांव हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में 14 आतंकवादियों की सूची जारी की थी और उनके घर भी गिरा दिए गए थे। सुरक्षा रिकॉर्ड के मुताबिक, जाकिर 2024 से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है, जबकि लतीफ पिछले साल LeT में शामिल हुआ था।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया ‘3ई’ अभियान शुरू, अब चालान के साथ पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ



नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में सड़क हादसों को कम करने और यातायात अनुशासन मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 3ई यानी एजुकेशन (शिक्षा), एनफोर्समेंट (प्रवर्तन) और एनकरेजमेंट (प्रोत्साहन) पर आधारित एक महीने का

“जन जागृति अभियान” शुरू किया है। अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ

अधिकारी के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना है ताकि सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। पूरे

महीने राजधानी के प्रमुख चौराहों, स्कूलों, कालेजों, बाजारों, कारपोरेट कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

दूसरे चरण एनफोर्समेंट के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, रेड लाइट जंप करने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रोड सेफ्टी चैंपियन होंगे सम्मानित

तीसरे चरण एनकरेजमेंट के अंतर्गत नियमों का लगातार पालन करने वाले वाहन चालकों, साइकिल चालकों, यात्रियों और अन्य जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ताओं को रोड सेफ्टी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने से अन्य लोग भी नियमों के पालन के लिए प्रेरित होंगे।

खत्म हुआ सन्नाटा, गूंजेंगी मिलों की मशीनें 10 जुलाई तक खुल जाएंगी बंगाल की सभी बंद जूट मिलें



कोलकाता, एजेंसी। बंगाल में बंद पड़ी सभी जूट मिलों को 10 जुलाई तक फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को कोलकाता के न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग में श्रम मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जूट मिल प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग दौर की वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में श्रम राज्यमंत्री भास्कर भट्टाचार्य, विशेष श्रम आयुक्त आशीष सरकार तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्द्धमान जिलों की इंडिया जूट, हेस्टिंग्स, गोदोलपाड़ा, एम्पायर, लूमटक्स, शक्तिमण्ड और हावड़ा जूट मिलों के प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में तय किया गया कि संबंधित जूट मिल प्रबंधन 10 जुलाई तक सस्पेंशन आफ वर्क वापस लेने की अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद सबसे पहले अनुरक्षण का कार्य शुरू होगा और 16 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से उत्पादन आरंभ किया जाएगा।

हिमाचल सरकार 3.41 लाख युवाओं को लौटाएगी रद्द हुई भर्तियों का आवेदन शुल्क



हमीरपुर, एजेंसी। पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से वर्ष 2022 में विभिन्न विभागों के पदों के लिए आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है। राज्य सरकार ने रद्द हो चुकी 80 पोस्ट कोड की भर्तियों के लिए जमा करवाया गया आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 3,41,742 अभ्यर्थियों को लगभग 4.27 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे। इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। वर्ष 2022 में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर ने 80 पोस्ट कोड के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में 1,423 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए थे। इनमें जेओए (आईटी), ऑडिट, फार्मासिस्ट, फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, तकनीकी शिक्षा सहित कई अन्य विभागों के पद शामिल थे। इन भर्तियों के लिए प्रदेशभर से 3.41 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और निर्धारित आवेदन शुल्क भी जमा कराया। इसी दौरान भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। इसके बाद भर्ती व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए और आयोग के माध्यम से जारी सभी 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रियाएं रद्द कर दी गईं।

आयोग भंग होने से फंसा रह गया आवेदन शुल्क का पैसा: भर्ती रद्द होने के बाद हजारों पद रिक्त रह गए और लाखों अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क भी आयोग के पास जमा रह गया। अब राज्य सरकार ने इन सभी अभ्यर्थियों को उनका आवेदन शुल्क वापस करने का फैसला लिया है। इसके लिए करीब 4.27 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे।

अब नए सिरे से होंगी भर्तियां: वहीं, जिन पदों की भर्ती रद्द हुई थी, उन्हें भविष्य में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से दोबारा भरा जाएगा। हालांकि नई भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसे लेकर सरकार ने अभी कोई समय सीमा घोषित नहीं की है।

जंगल के बीच बस में गूंजी किलकारी: यात्रियों ने कराया सुरक्षित प्रसव, इलाज के लिए जुटाए नौ हजार रुपये

कोरबा, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के कोरबा से पटना जा रही एक निजी बस में सोमवार देर रात यात्रियों की सुझबुझ से एक महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। साथ ही इलाज के लिए महिला को नौ हजार भी दिए। करीब 35 यात्रियों को लेकर निकली बस अंबिकापुर पार कर बलरामपुर की ओर बढ़ रही थी। रात करीब साढ़े 11 बजे कोरबा निवासी सुनती देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह पति के साथ बिहार स्थित ससुराल जा रही थी। यह देख चालक ने बस को सड़क किनारे रोक दिया। यात्री सुनती बाई व अन्य महिलाओं ने सीमित संसाधनों के बीच गर्भवती का सुरक्षित प्रसव कराया। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद नवजात के रोने की आवाज गूंजते ही बस में मौजूद यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पता चला कि दंपती के पास इलाज व अन्य जरूरी खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। देखते ही देखते नौ हजार रुपये एकत्र हो गए। इसके बाद चालक बस को बलरामपुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां मां और नवजात को भर्ती कराया गया।

ज्योतिर्लिंग और धार्मिक स्थलों का दर्शन को चलेगी दो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन

गोरखपुर, एजेंसी। दक्षिण और पश्चिम भारत के ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं स्ट्रेच्यू ऑफ यूनिटी दिखाने के लिए आईआरसीटीसी गोरखपुर जंक्शन से दो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेनें 31 जुलाई और 17 अगस्त को चलाई जाएंगी। रास्ते में 11 स्टेशनों से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी। ट्रेन से सफर के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कांपोशन) के एजीएम वायु नंदन शुक्ला ने बताया कि दोनों ट्रेनों से यात्रा के लिए शुल्क का भुगतान बैंक से ईएमआई के माध्यम से किया जा सकता है।

जोधपुर एम्स के डॉक्टरों का कमाल: सात साल के मासूम के पेट से निकाला 3.7 किलो का कैंसर ट्यूमर



जोधपुर, एजेंसी। एम्स जोधपुर के चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए सात वर्षीय बच्चे के शरीर से 3.7 किलोग्राम वजन का ट्यूमर निकालकर उसे नया जीवन दिया। बच्चा पिछले लगभग चार वर्षों से पेट के दाहिने हिस्से में लगातार बढ़ रही सूजन से परेशान था। एम्स में किए गए सीटी स्कैन में पता चला कि ट्यूमर का आकार लगभग 24 म 21 म 18 सेंटीमीटर हो चुका था। यह पूरी दाहिनी किडनी को नष्ट कर पेट के अधिकांश हिस्से में फैल चुका था। ट्यूमर के कारण लीवर, अग्न्याशय, आंतें और मूत्राशय अपनी सामान्य स्थिति से हट गए थे। सर्जरी के दौरान चिकित्सकों ने दाहिनी किडनी तथा पूरी मूत्रवाहिनी (यूरेटर) को ट्यूमर सहित निकाल दिया। इस उपलब्धि पर डॉ. गहूल सक्सेना ने कहा कि यह हमारे संस्थान में बच्चों पर की गई सबसे चुनौतीपूर्ण सर्जरी में से एक थी। ट्यूमर का आकार अत्यंत बड़ा था और उसने शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रक्त वाहिका को प्रभावित कर दिया था। इसकाश्रेय पूरी टीम के सांघुहिक प्रयासों को जाता है।

ऐसा क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पास खाली कराना पड़ा भारतीय मिशन मौके पर पहुंचे मेयर ममदानी

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के पास स्थित भारत के स्थायी मिशन के परिसर को मंगलवार को एहतियातन खाली करा लिया गया। इसकी वजह पास में निर्माणाधीन एक 37 मंजिला इमारत में आए गंभीर संरचनात्मक दोष हैं, जिससे उसके आंशिक रूप से ढहने का खतरा पैदा हो गया है। मिडटाउन मैनहट्टन के इस इलाके में कई इमारतों को भी खाली कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और भारतीय मिशन में तैनात सभी राजनयिक तथा उनके परिवार सुरक्षित हैं।

भारतीय मिशन को तुरंत खाली कराने की नौबत आखिर क्यों आई: भारत का स्थायी मिशन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से महज एक ब्लॉक की दूरी पर स्थित है। इस इमारत में मिशन के कार्यालयों के साथ-साथ भारतीय राजनयिकों और अन्य अधिकारियों के आवास भी हैं। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक सभी भारतीय अधिकारी और उनके परिवार सुरक्षित हैं तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

बनाया गया था भारतीय



को दूरी पर स्थित है। इस इमारत में मिशन के कार्यालयों के साथ-साथ भारतीय राजनयिकों और अन्य अधिकारियों के आवास भी हैं।

एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक सभी भारतीय अधिकारी और उनके परिवार सुरक्षित हैं तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

मिशन: न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मिशन 27 मंजिला लाल ग्रेनाइट की इमारत में संचालित होता है, जिसका निर्माण वर्ष 1993 में हुआ था। इस भवन का डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। यह इमारत सेकंड एवेन्यू के पास 43वीं और 44वीं स्ट्रीट के बीच स्थित है।

मेयर ने हालात को 'बेहद गंभीर' क्यों बताया: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने घटना को 'बेहद गंभीर' बताया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है और निर्माण स्थल पर मौजूद सभी मजदूरों का पता लगा लिया गया है। ममदानी के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 8 बजे (स्थानीय समय) न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट को मैनहट्टन की 42वीं स्ट्रीट पर

सेकंड और थर्ड एवेन्यू के बीच स्थित एक सक्रिय निर्माण स्थल पर संरचनात्मक समस्या की सूचना मिली थी। मेयर ममदानी ने कहा कि इमारत अभी भी अस्थिर बनी हुई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक प्रशासन इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं कर देता, तब तक यहां आने से बचें।

क्या ह मुख्यालय के आसपास की

कई अहम इमारतें भी खतरे में हैं जिस इमारत में यह समस्या सामने आई है, उसके ठीक सामने भारतीय मिशन स्थित है। आसपास कई देशों के संयुक्त राष्ट्र मिशन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालय, बड़े होटल, रेस्तरां, आवासीय इमारतें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं।

लॉरेंस गैंग के गुर्गों कितने देशों में फैले, अमेरिका-कनाडा में क्या आरोप लगे

वॉशिंगटन, एजेंसी। कभी पंजाब और उत्तर भारत तक सीमित माना जाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब कई देशों के लिए भी मुसीबत बन गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी इस गैंग से निपटने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। अमेरिका में दाखिल एक संघीय आरोपपत्र और हाल में अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप में हुई कार्रवाई ने ये तो साफ कर दिया है कि यह नेटवर्क अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि जेल में बंद रहने के बावजूद बिश्नोई अपने सहयोगियों के जरिए कई देशों में आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा। जेल में होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बरकरार रखे हैं। हत्या, रंगदारी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में उसके नेटवर्क की भूमिका की जांच की जा रही है। इसी क्रम में कई देशों में समन्वित कार्रवाई के दौरान गैंग से जुड़े 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बिश्नोई के अतीत में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं। फिलहाल अमेरिका में उस पर



क्या कार्रवाई हुई।

अमेरिकी चार्जशीट में आखिर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं: एक जुलाई को अमेरिका की संघीय ग्रैंड जुरी ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नौ बिंदुओं वाला आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि पंजाब का रहने वाला 33 वर्षीय लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से भारत की जेल में बंद होने के बावजूद एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का संचालन करता रहा।

दस्तावेज के मुताबिक, उसने पहले छत्र

राजनीति के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन बाद में अपराध की दुनिया में उतर गया। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि उसने सोशल मीडिया, इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों के जरिए खुद को छवि आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि पंजाब का रहने वाला 33 वर्षीय लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से भारत की जेल में बंद होने के बावजूद एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का संचालन करता रहा।

दस्तावेज के मुताबिक, उसने पहले छत्र

जेल के भीतर से तस्करी कर लाए गए मोबाइल फोन और इंटरनेट आधारित कॉलिंग सिस्टम यानी वीओआईपी के जरिए अपने साथियों से संपर्क करता था। इन्हीं माध्यमों से हत्या, गोलीबारी, रंगदारी, अपहरण, ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के निर्देश दिए जाते थे।

क्या जेल में रहते हुए भी चलता रहा पूरा नेटवर्क: अमेरिकी दस्तावेज का सबसे बड़ा दावा यही है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क लगातार सक्रिय रहा।

अभियोजकों के अनुसार, गैंग के अलग-अलग देशों में मौजूद सदस्य सीधे लॉरेंस से संपर्क में रहते थे। निर्देश मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर वारदातों को अंजाम दिया जाता था। इसके लिए इंटरनेट कॉलिंग, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप और दूसरे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था। चार्जशीट के मुताबिक, गैंग ने केवल अपराध ही नहीं किए, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों का प्रचार भी किया। हिंसक घटनाओं के वीडियो, धमकी भरे

संदेश और जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट जारी कर लोगों में डर पैदा किया जाता था। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि इसका मकसद रंगदारी वसूलने के लिए भय का माहौल बनाना था।

गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की भूमिका क्यों मानी जा रही अहम: अमेरिकी आरोपपत्र के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने संगठन की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां कुछ भरोसेमंद सहयोगियों को सौंप रखी थीं।

इनमें सबसे प्रमुख नाम सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का है। चार्जशीट के अनुसार, गोल्डी बराड़ उत्तर अमेरिका में गैंग की गतिविधियों की निगरानी करता था। जबकि राजस्थान के रहने वाले रोहित गोदारा को यूरोप में नेटवर्क संचालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनके अलावा सुखराज सिंह कंग का भी नाम प्रमुख सहयोगियों में शामिल है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई की ओर से फैसले लेते थे।

सिंगरौली में स्कॉर्पियो से 720 शीशी प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप जब्त, सीधी के युवक और नाबालिग को पुलिस ने दबोचा

मीडिया ऑडीटर,सिंगरौली (निप्र)। जिले की बरगवां थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 720 शीशी प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप बरामद की है इस मामले में पुलिस ने सीधी जिले के निवासी रजनीश विश्वकर्मा और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है जब किए गए वाहन और नशीली सिरप की कुल कीमत 12 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है पुलिस मामले की जांच कर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस के अनुसार बरगवां थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीधी जिले से एक स्कॉर्पियो वाहन में बड़ी मात्रा में

प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप सिंगरौली लाई जा रही है सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मझिगवां-आजादपुर मार्ग पर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू कर दी कुछ देर बाद बताए गए हुलिए की स्कॉर्पियो वहां पहुंची जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली तलाशी के दौरान वाहन से 720 शीशी प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप बरामद हुई मौके पर मौजूद दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने कथित तौर पर स्वीकार किया कि यह खेप सीधी से सिंगरौली लाकर बेचने की योजना थी।

पुलिस ने आरोपी रजनीश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया जबकि साथ मौजूद नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिरक्षा में लिया गया है नाबालिग को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा वहीं



तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। बरगवां थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप की यह खेप किसने भेजी थी, इसका वास्तविक सप्लायर कौन है और सिंगरौली में इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था जांच एजेंसियां इस तस्करी

हल्की खरोंच के विवाद में ट्रक चालक का पीछा, जियो पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर दबंगई के आरोप

जाती है लेकिन इस घटना में कुछ लोगों ने स्वयं कार्रवाई करने का प्रयास किया। आरोप है कि पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी तथा संचालक के रिश्तेदार ट्रक का पीछा करते हुए रतहरा से हरिहरपुर तक पहुंच गए प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पीछा करने वालों में कुछ लोग पेट्रोल पंप की वदीं पहले हुए थे उन्होंने रास्ते में ट्रक को रोकने का प्रयास किया और चालक पर विवाद सुलझाने के नाम पर दबाव बनाया इस दौरान सड़क पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई जिससे अन्य वाहन चालकों और रहगोरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के दौरान ट्रक चालक को कई लोगों ने घेर लिया था जिससे वह भय और दबाव की स्थिति में

दौरा शुरू हो गया है हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रतहरा स्थित जानकी फिलिंग पेट्रोलियम के समीप एक ट्रक और कार के बीच हल्का संपर्क हुआ जिससे कार पर मामूली खरोंच आने की बात सामने आई स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में सामान्यतः पुलिस को सूचना देकर कानूनी प्रक्रिया अपनाई



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले के रतहरा स्थित जानकी फिलिंग पेट्रोलियम (जियो पेट्रोल पंप) के पास एक ट्रक और कार के बीच हुई मामूली खरोंच की घटना ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और संचालक के रिश्तेदारों पर ट्रक चालक का कई किलोमीटर तक पीछा करने तथा बीच रास्ते में रोककर दबाव बनाने के आरोप लगे घटना के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाओं का

दिखाई दे रहा था कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी आरोप है कि जब आसपास मौजूद नागरिकों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश देकर मामला शांत करने का प्रयास किया तब उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया इससे मौके पर मौजूद लोगों में नाजगगी देखी गई। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि यदि किसी वाहन से दुर्घटना होती है या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए कानून में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है और उसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई होती है उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा कानून को अपने हाथ में लेना उचित नहीं है और इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल 9 और 10 जुलाई को सीधी दौरें पर, विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और विभागीय समीक्षा करेंगे



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल 9 और 10 जुलाई को सीधी जिले के प्रवास पर रहेंगे अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान वे जिले में विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन,

लोकार्पण, हितलाभ वितरण कार्यक्रमों में शामिल होंगे इसके साथ ही अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री 9 जुलाई को सुबह 9 बजे चुरहट सर्किट हाउस पहुंचेंगे सुबह 10:45 बजे वे जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे इसके बाद सुबह 11:15 बजे जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत कुआं में पहुंचकर पांच आंगनबाड़ी भवनों का भूमिपूजन करेंगे। इसके बाद सुबह 11:45 बजे नगर पंचायत रामपुर नैकिन के सामुदायिक भवन में आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम में

शामिल होंगे और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित करेंगे दोपहर 1 बजे हनुमानगढ़ तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे इसके बाद दोपहर 1:30 बजे सेमरिया तहसील कार्यालय भवन का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2 बजे उच्च विश्राम गृह सीधी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित है इसके बाद दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में 9 जुलाई को जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में 9 जुलाई 2026 को जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी बैठक में जिले के विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। अपर कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैठक का आयोजन 9 जुलाई को अपराह्न 3 बजे जिला पंचायत सीधी के सभाकक्ष में किया जाएगा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे और अपने-अपने विभागों से

संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अपर कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे बैठक में उपस्थित होने से पहले अपने विभाग की योजनाओं, प्रगतिरत कार्यों, उपलब्धियों और लॉन्च प्रकरणों से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक स्थल पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की स्थिति, विकास कार्यों की प्रगति, विभागीय उपलब्धियों और आमजन से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

मझौली के ग्राम ठोंगा में कृषक पाठशाला आयोजित, किसानों को जैविक खेती और उन्नत कृषि तकनीकों का दिया प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती और बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड मझौली द्वारा ग्राम पंचायत ठोंगा में कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया कृषि वर्ष 2026-27 के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों और महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों को खरीफ फसलों की रोपाई, वैज्ञानिक प्रबंधन, जैविक खेती तथा प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किसानों को खरीफ



फसलों की बेहतर पैदावार के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान की इस दौरान फसल की तैयारी, रोपाई के सही तरीके, पौधों की देखभाल, रोग नियंत्रण और उत्पादन बढ़ाने के उपायों के बारे में बताया गया किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जैविक

संसाधनों से तैयार किए जाने वाले प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण और उपयोग की जानकारी भी दी गई प्रशिक्षण के दौरान ब्रह्माव्र, नीमाख सहित अन्य जैविक उपायों के बारे में बताया गया किसानों को समझाया गया कि इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से खेती की लागत कम की जा सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाए रखा जा सकता है।

रीवा में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त, अस्पताल चौक से शुरू होगी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की पायलट पहल



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नागरिक सुविधाओं को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने बुधवार को शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में शामिल अस्पताल चौक का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध नागरिक सुविधाओं

एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल चौक को पायलट क्षेत्र के रूप में विकसित करते हुए यहां स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, पेयजल, अतिक्रमण नियंत्रण और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहर के ऐसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर

विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक, मरीज, व्यवसायी, बाहर से आने वाले लोग और अन्य वर्ग के लोग पहुंचते हैं इन स्थानों पर सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाएगी अस्पताल चौक के बाद इसी मॉडल को शहर के अन्य प्रमुख स्थलों पर भी लागू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने अस्पताल चौक के समीप स्थित खाली भूखंड का अवलोकन किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां लेबर स्टैंड और ऑटो स्टैंड विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि सुबह के समय सड़क किनारे खड़े होने वाले श्रमिकों और ऑटो चालकों को व्यवस्थित स्थान मिल सके।

इससे सड़क पर होने वाली अनावश्यक भीड़ और यातायात बाधित होने की समस्या को कम किया जा सकेगा उन्होंने अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने ड्रॉप एंड गो प्वाइंट विकसित करने के निर्देश भी दिए इससे मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिलेगी तथा अस्पताल चौक पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग और जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। नगर निगम आयुक्त ने अस्पताल चौक क्षेत्र में संचालित टेला-गुम्टियों का सर्वे कर उनकी सूची तैयार करने और निर्धारित सीमा के भीतर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बनाई जाए लेकिन यातायात और नागरिक सुविधाओं में बाधा नहीं आनी

चाहिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रय स्थल का भी जायजा लिया उन्होंने वहां लगी क्षतिग्रस्त जाली की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए ताकि किसी दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके साथ ही आश्रय स्थल में दैनिक पंजी संभारित करने, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की लगातार चालू रखने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने दीनदयाल रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की उन्होंने भवन के रंगरोशन और आवश्यक नवीनीकरण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए ताकि हितग्राहियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि

अस्पताल चौक क्षेत्र में सुबह की पाली में जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए साथ ही इन व्यवस्थाओं की निर्यामित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना नगर निगम की प्रमुख जिम्मेदारी है निगम आयुक्त ने अतिक्रमण नियंत्रण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अतिक्रमण निरोधक दल सक्रिय रूप से अभियान चलाएगा इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा।

एक और दो रुपये के सिक्के पूरी तरह वैध मुद्रा, लेन-देन में स्वीकार नहीं करने पर होगी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला प्रशासन ने एक और दो रुपये के सिक्कों को लेकर फैल रही अफवाहों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी वैध सिक्के पूर्ण रूप से मान्य मुद्रा हैं प्रशासन ने नागरिकों, व्यापारियों और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे इन सिक्कों को लेन-देन में बिना किसी संकोच के स्वीकार करें जिला दंडाधिकारी रीवा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध सिक्कों को किसी उचित कारण के बिना स्वीकार करने से इंकार करना और इनके संबंध में भ्रामक अफवाह फैलाना जनहित के प्रतिकूल है ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी नागरिकों, व्यापारियों, दुकानदारों, व्यावसायिक संस्थानों, परिवहन संचालकों, सेवा प्रदाताओं और बैंक शाखाओं को यह

सुनिश्चित करना होगा कि एक रुपये और दो रुपये के सिक्के देशभर में प्रचलित वैध मुद्रा हैं इन सिक्कों को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी धारा 223 के अंतर्गत शासकीय आदेश की अवज्ञा करने पर परिस्थितियों और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रशासन का कहना है कि समय-समय पर सेशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सिक्कों की वैधता को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की जाती है जिससे आम नागरिकों की परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए केवल भारतीय रिजर्व बैंक और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है।

वार्ड-22 में जलभराव से घरों में घुसा बारिश का पानी, नालियां और टूटी पुलिया बनीं परेशानी का कारण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। लगातार हो रही बारिश ने सीधी नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है शहर के वार्ड क्रमांक-22 में जाम नालियों और क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण बारिश का पानी कई घरों में घुस गया जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव से घरों में रखा फर्नीचर, कपड़े, राशन और अन्य घरेलू सामान भीगकर खराब हो गया प्रभावित परिवारों का कहना है कि नगर पालिका से कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है वार्डवासियों के अनुसार क्षेत्र में सड़क पर बनी छोटी पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है पुलिया टूटने के कारण नालियों का कचरा वहीं जमा हो जाता है जिससे पानी की निकासी बाधित होती है और पूरा इलाका जलभराव की चपेट में आ जाता है लोगों ने बताया कि इस पुलिया की मरम्मत की मांग भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार सुबह नगर पालिका के नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) महमूद हसन मौके पर पहुंचे उनके निर्देश पर कर्मचारियों ने जाम नालियों की सफाई कर जल निकासी की व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल नालियों की सफाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है वार्डवासियों के अनुसार क्षेत्र में सड़क पर बनी छोटी पुलिया लंबे समय से क्षतिग्रस्त है पुलिया टूटने के कारण नालियों का कचरा वहीं जमा हो जाता है जिससे पानी की निकासी बाधित होती है और पूरा इलाका जलभराव की चपेट में आ जाता है लोगों ने बताया कि इस पुलिया की मरम्मत की मांग भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

शर्मसार हैं हम : बारह साला बच्ची पर हैवानियत का कहर

अब आए दिन देश के प्रिंट मीडिया से लेकर अन्य सूचना माध्यमों में यौन अपराधों की विचलित करने वाली घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। यौन लिप्साओं का यह विस्फोट विचलित करने वाला है। कोई निर्भया, किसी के साहस के बूते अपने साथ हुए अन्याय को उजागर कर देती है, वहीं देश की अनेक निर्भयाएं यौन हिंसा व क्रूरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में त्रास झेलने को अभिशप्त हो जाती हैं। हाल की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन

बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारहईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे में बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली

है। जनाक्रोश के चलते प्रशासन ने न केवल 18 लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि उन होटलों को भी ध्वस्त किया गया जहां अलग-अलग जगहों में बच्चों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया गया। निस्संदेह, मोबाइल के बढ़ते हस्तक्षेप से परिवार संस्था की चूल् में हिली नजर आती हैं। कथित सोशल मीडिया समाज में विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। श्रीगंगानगर की

बारह वर्षीय लड़की शहर से सौ किमी दूर अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे वहां दुराचार करता है। वहां से देर रात शहर लौटने पर एक क्विशेवाले के झांसे में आकर होटल पहुंचती है और फिर उसके साथ दुराचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। परिजनों के लापता किशोरी के तलाश में थाने पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आती हैं, फिर उसे मुक्त कराया जाता

है। निस्संदेह, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। इस राक्षसी कृत्य से उद्बलित लोग श्रीगंगानगर की सड़कों पर उतर आए। धुब्ध लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कानून के रखवालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जनाक्रोश को देखते हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि भारतीय समाज में हो रहे यौन लिप्साओं के विस्फोट की वजह क्या है? ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? हवस के भूखे भेड़िए न उग्र देखते हैं, न किसी

बेटी की बेबसी। उस किशोरी के साथ हुई बर्बरता के बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। जो शायद ही जीवनभर इस त्रासदी से उबर पाये। कहीं न कहीं इंटरनेट व सोशल मीडिया पर यौन स्वच्छंदता की पश्चिम की आंधी हमारे समाज को पतित कर रही है। हमारे परंपरागत शुचिता के रिशतों को तार-तार करके निरंकुश यौन व्यवहार को तार्किक बताने की साजिश रची जा रही है। हम बच्चों को रामराज के संस्कार देते हैं, जबकि समाज में दानवराज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है।

साणंद का सेमीकंडक्टर केंद्र, आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान

सौरभ तार्षणय

 गुजरात के साणंद में सीजी सेमी की आउटसोर्संड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का संचालन केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम है। आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर होती जा रही है, ऐसे समय में भारत का इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चार जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्संड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया। ओएसएटी सुविधा का कार्य चिप निर्माण के बाद उनकी असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण करना होता है। यह सेमीकंडक्टर उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक भारत इस क्षेत्र में लगभग पूरी तरह विदेशी कंपनियों और आयातित चिप्स पर निर्भर रहा है, जिससे वैश्विक संकट या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में देश के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र प्रभावित होते रहे हैं। साणंद में स्थापित यह इकाई इस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। करीब 7,600 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित यह परियोजना भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक नई पहचान दिलाने की क्षमता रखती है। यह संयंत्र ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ऊर्जा क्षेत्र के लिए चिप्स की पैकेजिंग और परीक्षण करेगा। इससे देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों को नई गति प्राप्त होगी।
 इस परियोजना का एक बड़ा लाभ रोजगार सृजन के रूप में सामने आएगा। उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के विकास से इंजीनियरों, तकनीशियनों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इससे देश के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होगा, जो भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायक बनेगा। आने वाले वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होने की संभावना है। साणंद पहले ही ऑटोमोबाइल और विनिर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। अब सेमीकंडक्टर उद्योग के आगमन से यह क्षेत्र भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित हो सकता है। यहां अन्य वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति, निवेश और अनुसंधान गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उद्योग रणनीतिक महत्व रखता है। कोविड महामारी और अंतरराष्ट्रीय तनावों के दौरान दुनिया ने चिप्स की कमी के दुष्प्रभावों को देखा है। ऐसे में भारत का अपना सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी आवश्यक है। साणंद का ओएसएटी केंद्र इस दिशा में भारत के आत्मविश्वास और दूरदर्शी नीति का प्रतीक है।निस्संदेह, गुजरात के साणंद में स्थापित सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार, निर्यात वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। यह केवल एक उद्योग की शुरुआत नहीं, बल्कि विकसित भारत के उस स्वप्न की नींव है जिसमें देश विश्व की उन्नत तकनीकी शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देगा।

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्वक स्तरपर भारत में प्रत्येक वर्ष जुलाई का महीना लाखों करोड़ों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत का प्रतीक होता है। नई कक्षाएँ,नए सपने, नई पुस्तकें,नई वर्दी और नई उम्मीदें, ये सब मिलकर शिक्षा का उत्सव रचते हैं। किंतु इसी उत्सव के बीच एक ऐसी समस्या लगातार गहराती जा रही है,जो शिक्षा के मूल उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। देश के अनेक निजी विद्यालयों में अभिभावकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष दुकान अथवा स्वयं विद्यालय से ही पुस्तकें, कॉपीयों, यूनिफॉर्म, जूते, बैग तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतें वर्षों से सामने आती रही हैं।इससे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन से हटकर व्यावसायिक गतिविधि का रूप लेता दिखाई देता है। 2 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में शालेय शिक्षण मंत्री ने इस विषय पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र विद्यार्थी तक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में ही आवश्यक सामग्री समय पर पहुँचाना है। यदि किसी जिले या विद्यालय में वितरण में देरी अथवा अनियमितता होती है, तो उसकी जिम्मेदारी और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक विशेष दुकान से पुस्तकें, यूनिफॉर्म या अन्य शाला सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र यह मानता हू कि यह वक्तव्य केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नीति- संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए।दरअसल, भारत का संविधान शिक्षा को समान अवसर का आधार मानता है। शिक्षा का अधिकार केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना भी राज्य की जिम्मेदारी है जिसमें आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। यदि किसी अभिभावक को बाजार में उपलब्ध समान गुणवत्ता की पुस्तकें या यूनिफॉर्म कम कीमत पर मिल सकती हैं, फिर भी उसे विद्यालय द्वारा निर्धारित विक्रेता से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है,तो यह प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता अधिकार और शिक्षा की नैतिकता, सटीक रूप से तीनों के विरुद्ध है। साथियों, देश के अनेक शहरों और कस्बों में यह देखा गया है कि कुछ विद्यालय विशेष प्रकाशकों से समझौता कर ऐसी पुस्तकें निर्धारित कर देते हैं जो सामान्य बाजार में उपलब्ध नहीं होतीं।कई विद्यालय अपनी अलग अभ्यास



पुस्तिकाएँ भी अनिवार्य कर देते हैं। इसी प्रकार यूनिफॉर्म के लिए भी एक निश्चित दुकान तय कर दी जाती है। परिणामस्वरूप अभिभावकों के पास विकल्प समाप्त हो जाता है और उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार एक ही गुणवत्ता की सामग्री खुले बाजार में काफी कम मूल्य पर उपलब्ध होती है, लेकिन विद्यालय की शर्तों के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाता।भारत जैसे देश में,जहाँ बड़ी संख्या में परिवार मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग से आते हैं, शिक्षा पहुँचाने वाला अतिरिक्त व्यय परिवार की आर्थिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कई अभिभावकों को बच्चों की फीस, परिवहन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य खर्चों के लिए त्रुष्टा लेना पड़ता है। यदि शैक्षणिक सामग्री की खरीद में प्रतिस्पर्धा और विकल्प समाप्त कर दिए जाएँ, तो यह आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है, न कि आर्थिक असमानता को और गहरा करना। साथियों, शासकीय विद्यालयों की स्थिति इससे भिन्न होते हुए भी चुनौतियों से मुक्त नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें,यूनिफॉर्म,बैग तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बड़ी धनराशि खर्च करती हैं।कई राज्यों में वितरण प्रक्रिया में देरी,अपूर्ति संबंधी समस्याएँ अथवा प्रशासनिक लापरवाही जैसी शिकायतें सामने आती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री द्वारा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि निर्धारित समय पर सामग्री विद्यार्थियों तक पहुँचेगी, तभी सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।आज आवश्यकता केवल सामग्री

उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी है। यदि पुस्तकें सत्र शुरू होने के कई सप्ताह बाद मिलती हैं, तो विद्यार्थी प्रारंभिक अध्ययन से वंचित हो जाते हैं। यदि यूनिफॉर्म समय पर नहीं मिलती, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सामाजिक असहजता का सामना करना पड़ता है। इसलिए वितरण व्यवस्था का वैज्ञानिक और डिजिटल प्रबंधन समय की आवश्यकता है।साथियों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। निजी विद्यालयों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन शिक्षा सेवा और व्यावसायिक गतिविधि के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अधिकारिा निजी विद्यालय नियमों की गलत कार्यप्रणालियाँ पूरे निजी शिक्षा क्षेत्र की छवि को प्रभावित करती हैं। इसलिए नियमों का समान और निष्पक्ष पालन आवश्यक है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यालय केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने का केंद्र नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी निर्माण करते हैं। यदि विद्यालय स्वयं पारदर्शिता, निष्पक्षता और उपभोक्ता अधिकारों का अपनी समान नहीं करेगे, तो विद्यार्थियों में इन मूल्यों का विकास कैसे होगा? शिक्षा संस्थानों का स्वतंत्रता सीमित की जाती है, तो यह निष्पक्ष पाठ होता है। साथियों, अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी विद्यालय का दबाव बनाया जाता है, तो अभिभावकों को सामूहिक रूप से विद्यालय प्रबंधन से सवाद करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम

प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष शिकायत भी प्रस्तुत की जा सकती है। जागरूक नागरिक ही पारदर्शी व्यवस्था की नींव होते हैं।आज डिजिटल तकनीक इस समस्या का व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है। प्रत्येक विद्यालय अपनी पुस्तक सूची, यूनिफॉर्म का डिजाइन, आवश्यक सामग्री और उनकी विशिष्टताएँ सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध करा सकता है। इससे अभिभावक किसी भी अधिकृत विक्रेता से निर्धारित मांग हैं। साथियों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। निजी विद्यालयों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन शिक्षा सेवा और व्यावसायिक गतिविधि के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। अधिकारिा निजी विद्यालय नियमों की गलत कार्यप्रणालियाँ पूरे निजी शिक्षा क्षेत्र की छवि को प्रभावित करती हैं। इसलिए नियमों का समान और निष्पक्ष पालन आवश्यक है।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यालय केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने का केंद्र नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी निर्माण करते हैं। यदि विद्यालय स्वयं पारदर्शिता, निष्पक्षता और उपभोक्ता अधिकारों का अपनी समान नहीं करेगे, तो विद्यार्थियों में इन मूल्यों का विकास कैसे होगा? शिक्षा संस्थानों का स्वतंत्रता सीमित की जाती है, तो यह निष्पक्ष पाठ होता है। साथियों, अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी विद्यालय का दबाव बनाया जाता है, तो अभिभावकों को सामूहिक रूप से विद्यालय प्रबंधन से सवाद करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम

पहचान होते हैं। अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए यदि अभिभावकों का विश्वास खो दिया जाए, तो संस्था की सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है।समाज के स्तर पर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देना है। विद्यालयों का मूल्यांकन केवल भवन, परिणाम या सुविधाओं से नहीं,बल्कि उनकी नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी होना चाहिए। जो विद्यालय अभिभावकों को विकल्प देते हैं, उचित मूल्य सुनिश्चित करते हैं और विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखते हैं, वे वास्तव में आदर्श शिक्षा संस्थान कहलाने के अधिकारी हैं।महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री द्वारा दिया गया संदेश इसी व्यापक राष्ट्रीय सोच का प्रतिनिधित्व करता है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जवाबदेही और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा अनिवार्य है। यदि इस भावना को सभी राज्य अपनाएँ और प्रभावी रूप से लागू करें, तो करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास और सटीकता से मजबूत होगा। साथियों, अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी यही बताते हैं कि विकसित देशों में अधिकांश विद्यालय आवश्यक सामग्री की सूची उपलब्ध कराते हैं, लेकिन खरीद का विकल्प अभिभावकों पर छोड़ते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, कीमतें नियंत्रित रहती हैं और परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं पड़ता। भारत भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाकर शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा जनहितकारी बना सकता है।शासन की जिम्मेदारी केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नियमित निरीक्षण, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, समयबद्ध जांच, दोषी संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई तथा शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक केवल दिशा-निर्देश पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगे। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह प्रश्न केवल कॉपी, पुस्तक, बैग या यूनिफॉर्म का नहीं है। यह प्रश्न शिक्षा के चरित्र का है। क्या विद्यालय ज्ञान के मंदिर बने रहेंगे या धीरे-धीरे बाजार का विस्तार बन जाएंगे? इसका उत्तर सरकार, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज- सभी को मिलकर देना होगा। जब प्रत्येक विद्यार्थी को समय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री मिले, अभिभावकों को खरीद की स्वतंत्रता प्राप्त हो, सरकारी योजनाओं का लाभ बिना विलंब पहुँचे और निजी विद्यालय पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करें, तभी भारत को शिक्षा व्यवस्था वास्तव में समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी और विश्वस्तरीय बन सकेगी। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है और यही विकसित भारत की मजबूत नींव भी।

विकास के साथ परमाणु रक्षा मजबूती जरूरी



की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में अब भारत को विकसित राष्ट्र और दुनिया की महाशक्ति बनाने के मद्देनजर और तेजी से आर्थिक विकास के साथ परमाणु हथियार मोचें पर आगे बढ़ना जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में दो हालिया रिपोर्टें उल्लेखनीय हैं। विश्व बैंक ने अपनी 'रिपोर्ट 2026' में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत होगी और उभरते हुए देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने

वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। दूसरी और दुनिया में हथियारों पर नजर रखने वाली ग्लोबल संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) की परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत परमाणु हथियार मोचें पर दुनिया में अभूतपूर्व तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया में पांचवें क्रम पर है। जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल 190 परमाणु वॉरहेड (पाकिस्तान-

170) हो गए हैं। भारत के पास एक साल पहले इसकी संख्या 180 थी। इनमें से 12 परमाणु बमों को उनके डिलीवरी सिस्टम जैसे मिसाइल, पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ दिया गया है। साथ ही उन्हें ऑपरेशनल फोर्स वाले बेस पर तैनात किया गया है। स्पष्ट है कि परमाणु हथियारों को अलग स्टोरेज फैसिलिटी में रखने की भारत की दशकों पुरानी नीति अब बदल गई है। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि शांति के जरूरत भारत अपनी परमाणु वॉरहेड को तैनात लॉन्चर से अलग रखता है। मिसाइलों को लगातार कैनिस्टर में रखने और समुद्र में डेटेरेंस पैट्रोलिंग (सुरक्षा के लिए गश्त) करने जैसे हालिया कदमों से संकेत मिलता है कि भारत शांति के समय में भी अपने कुछ वॉरहेड को लॉन्चर के साथ जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारतीय युद्धपोत, पनडुब्बी और दूसरे हथियारों में परमाणु हथियार हमेशा तैनात रहते हैं। वस्तुतः चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा तैयारी रणनीति के तहत यह एक असाधारण बदलाव है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक रक्षा व्यय से संबंधित ताजा

रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया में भारत रणनीतिक रूप से आर्थिक मजबूती के साथ रक्षा मजबूती के लिए रक्षा व्यय बढ़ाने वाले प्रमुख देश के रूप में उभर कर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एक ऐसे समय में जब भारत की सीमाएँ बढ़ती भूराजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर पहले से अधिक असुरक्षित और संवेदनशील हो गई हैं, तब भारत को न केवल दुनिया की आर्थिक शक्ति, अब बदल गई है। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि शांति के जरूरत भारत अपनी परमाणु वॉरहेड को तैनात लॉन्चर से अलग रखता है। मिसाइलों को लगातार कैनिस्टर में रखने और समुद्र में डेटेरेंस पैट्रोलिंग (सुरक्षा के लिए गश्त) करने जैसे हालिया कदमों से संकेत मिलता है कि भारत शांति के समय में भी अपने कुछ वॉरहेड को लॉन्चर के साथ जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारतीय युद्धपोत, पनडुब्बी और दूसरे हथियारों में परमाणु हथियार हमेशा तैनात रहते हैं। वस्तुतः चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा तैयारी रणनीति के तहत यह एक असाधारण बदलाव है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक रक्षा व्यय से संबंधित ताजा

एडमिनिस्ट्रैटिव काउंटी स्थापित की गई है। चीन हिंद महासागर में 'हिंटो ऑफ प्लस' नीति के जरिए भी भारत को चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारत चीन के हर विस्तारवादी कदम का लगातार कड़ा और बहुआयामी जवाब देते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष 2025 में भारत के द्वारा पाकिस्तान को पहलूपाण आतंकी हमले का जवाब देने के मद्देनजर जब 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तब पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन, तुर्किये और अजरबैजान का खतरनाक गठजोड़ सामने आया था। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन ने पाकिस्तान को साहबख स्पेसपोर्ट, उपग्रह के जरिए खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी। अब पाकिस्तान के द्वारा चीन के सहयोग से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार विकसित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता भी किया है। पिछले दिनों अमरीका की नेशनल इंटीलिजेंस डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत 'एनुअल ग्रेट असेसमेंट' रिपोर्ट 2026 में कहा गया है कि इस समय पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा परमाणु और पारंपरिक हथियारों का विस्तार भारत सहित दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

वस्तुतः चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा तैयारी रणनीति के तहत यह एक असाधारण बदलाव है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक रक्षा व्यय से संबंधित ताजा रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया में भारत रणनीतिक रूप से आर्थिक मजबूती के साथ रक्षा मजबूती के लिए रक्षा व्यय बढ़ाने वाले प्रमुख देश के रूप में उभर कर दिखाई दे रहा है...

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने किया सरेंडर, तीन साल बाद EOW के सामने हुए पेश



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले और अन्य आर्थिक अनियमितताओं की जांच के बीच कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने करीब तीन वर्ष बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बुधवार को वे रायपुर स्थित EOW कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जांच एजेंसी के समक्ष सरेंडर किया। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक EOW की ओर से उनके सरेंडर को लेकर

आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था जांच एजेंसियों के अनुसार रामगोपाल अग्रवाल का नाम कथित शराब घोटाले, कोल लेवी वसूली और कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले की जांच के दौरान सामने आया है उन पर आरोप है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते हुए कथित घोटाले से जुड़े धन को कांग्रेस के राजीव भवन तक मंगवाने में उनकी भूमिका रही इन आरोपों की अभी न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है और मामला जांच एवं अदालती प्रक्रिया के अधीन है सूत्रों के अनुसार सरेंडर से पहले



EOW ने रामगोपाल अग्रवाल के बेटे वैभव अग्रवाल से भी लंबी पूछताछ की। अधिकारियों ने उनसे पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके पिता के ठिकानों, आर्थिक लेन-देन, संपर्कों और कथित नेटवर्क से जुड़े कई सवाल पूछे हालांकि पूछताछ के बाद वैभव अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं की गई। एजेंसी अब रामगोपाल अग्रवाल के संपर्क में रहे अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाकर पूरे आर्थिक नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है जांच एजेंसियों के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल का नाम करीब 3,000 करोड़

रुपये के कथित शराब घोटाले, 450 करोड़ रुपये के कथित कोल लेवी वसूली मामले तथा 127 करोड़ रुपये के कथित कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले की जांच में सामने आया एजेंसियां इन मामलों में धन के प्रवाह, लाभार्थियों और कथित कमीशन नेटवर्क की जांच कर रही हैं बताया जा रहा है कि रामगोपाल अग्रवाल पिछले लगभग तीन वर्षों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। इस दौरान उनके देश और विदेश में जुड़ू है जांच एजेंसियों का आरोप है कि कोयला परिवहन करने वाले

उनकी लोकेशन और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही थीं। प्रवर्तन निदेशालय और EOW की जांच के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 के बीच राज्य की सरकारी शराब बिक्री व्यवस्था में कथित सिंडिकेट बनाकर अवैध शराब की बिक्री, कमीशनखोरी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के माध्यम से करीब 3,200 करोड़ रुपये का अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया मामले में कई आईएसएस अधिकारियों, आबकारी विभाग के अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। कथित कोल लेवी घोटाला वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोयला परिवहन को देश और विदेश में जुड़ू है जांच एजेंसियों का आरोप है कि कोयला परिवहन करने वाले

कारोबारियों से प्रति टन निर्धारित राशि अवैध रूप से वसूली गई जिससे लगभग 540 करोड़ रुपये की अवैध लेवी एकत्र की गई। वहीं, कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में वर्ष 2015 से 2023 के बीच धान मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में कथित अनियमितताओं का आरोप है। EOW के अनुसार नियमों के उल्लंघन कर चुनिंदा राइस मिलर्स को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया जिससे लगभग 127 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता हुई। फिलहाल तीनों मामलों की जांच जारी है। EOW और अन्य जांच एजेंसियां दस्तावेजों, आर्थिक लेन-देन और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही हैं रामगोपाल अग्रवाल के सरेंडर के बाद इन मामलों की जांच में नए तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है वहीं सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं तथा अंतिम निष्कर्ष अदालत के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होंगे।

ग्राम केल्हारी के सभी सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने अभियान तेज



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा जल गुणवत्ता संरक्षण अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत केल्हारी अंतर्गत ग्राम केल्हारी में स्थापित सभी सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया इस पहल का उद्देश्य जल स्रोतों को संक्रमण मुक्त बनाकर ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना और जलजनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निदेशन में विभाग की तकनीकी टीम और हैंडपंप टेक्नीशियनों ने विशेष अभियान चलाकर ग्राम के विभिन्न

सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित हैंडपंपों में निर्धारित मानकों के अनुसार क्लोरीनेशन किया। इस दौरान आत्मानंद विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे सभी हैंडपंपों को अभियान में शामिल किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ग्राम केल्हारी में कुल 12 सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन किया गया जिसमें प्रत्येक हैंडपंप में निर्धारित मात्रा में अनुसार 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग किया गया क्लोरीनेशन की प्रक्रिया से पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नियांत्रित किया जाता है जिससे जल की गुणवत्ता बेहतर होती है और लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो पाता है।

मोर गांव मोर पानी’ अभियान बना जल संरक्षण की नई मिसाल, 350 आजीविका डबरियां और 150 से अधिक तालाबों से बदलेगा ग्रामीण जल परिदृश्य



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संचालित ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान जिले में जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित इस अभियान के तहत अब तक 350 आजीविका डबरियां तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण

और विकास किया जा चुका है इन जल संरचनाओं से वर्षा जल का अधिकतम संचयन, भू-जल संवर्धन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण आजीविका को स्थायी मजबूती मिलने की उम्मीद है मानसून के दौरान प्राप्त होने वाले वर्षा जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इन जल संरचनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब दिखाई देने लगा है आजीविका डबरियां और सामुदायिक तालाब वर्षा

जल को संचित कर भू-जल स्तर बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराएंगे इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान फसल विविधीकरण की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे अभियान के तहत निर्मित 350 आजीविका डबरियां ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आय का नया माध्यम भी बनेंगी। इनका उपयोग मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन तथा अन्य आजीविका आधारित गतिविधियों में किया जा सकेगा इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे वहीं 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों के निर्माण और गहरीकरण से गांवों की जल संचयन क्षमता में

उल्लेखनीय वृद्धि होगी इन तालाबों का उपयोग सिंचाई, पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने भू-जल पुनर्भरण तथा पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा गर्मी के मौसम में जल संकट से राहत मिलने के साथ ही जल स्रोतों की स्थिरता भी बनी रहेगी। जिला प्रशासन के अनुसार यह अभियान केवल जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़कर जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों और ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है साथ ही निर्मित जल संरचनाओं के नियमित रखरखाव और संरक्षण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

इफको नैनो डीएपी से बढ़ा किसान का भरोसा, उर्वरक और बीज मिलने से खरीफ की तैयारी हुई आसान



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत उर्वरकों का उपयोग किसानों की खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर क्षेत्र के ग्राम कोयडोल निवासी किसान शंकर यादव ने इस खरीफ सीजन में इफ्को नैनो डीएपी का उपयोग कर नई कृषि तकनीक अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों की उपलब्धता से उन्होंने खरीफ फसल की तैयारी निर्धारित

समय पर पूरी कर ली है और बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई है आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जनकपुर द्वारा किसान शंकर यादव को कृषि कार्य के लिए आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध कराए गए। समिति से उन्हें इफ्को डीएपी (18:46) की एक बोरे, इफ्को नैनो डीएपी की एक बोतल, दो बोरी नीम लेपित यूरिया तथा 30 किलोग्राम एमटीए-1156 प्रमाणित धान बीज प्रदान किए गए इन संसाधनों की समय पर उपलब्धता से उन्होंने खेतों की तैयारी पूरी कर खरीफ फसल की बुवाई भी समय पर शुरू कर दी। किसान शंकर यादव ने बताया कि इस बार उन्होंने पारंपरिक उर्वरकों के साथ इफ्को नैनो डीएपी का भी उपयोग करने का निर्णय लिया है उनके अनुसार नैनो डीएपी आधुनिक तकनीक पर आधारित उर्वरक है जो कम मात्रा में ही फसल को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

मनेन्द्रगढ़ में विदेशी मदिरा दुकान के लिए भवन किराये पर लेने तीसरी लघु निविदा जारी

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) ने जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अंतर्गत संचालित विदेशी मदिरा दुकान, मनेन्द्रगढ़ के संचालन के लिए उपयुक्त भवन किराये पर लेने हेतु तृतीय लघु निविदा जारी की है। नगर पालिका क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के भीतर स्थित भवनों के स्वामियों से तकनीकी एवं वित्तीय प्रहण करने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक किराये पर लिया जाएगा। जिला आबकारी कार्यालय द्वारा जारी नैनो निविदा सूचना के अनुसार इच्छुक भवन स्वामी एवं निविदाकार अपनी तकनीकी बिड और प्राइस बिड अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं निविदाएं 14 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा की जा सकेंगी निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा सभी प्राप्त तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं को 14 जुलाई 2026 को शाम 4:30 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा इस प्रक्रिया का उद्देश्य भवन चयन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना है निविदा से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें, पात्रता, भवन

की आवश्यकताओं तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है इच्छुक आवेदक अवकाश के दिनों को छोड़कर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा यह बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पक्ष में देय होगा चाहिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही निविदा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन आवेदकों ने पूर्व में निविदा प्रपत्र खरीदे हैं वे भी उन्हीं प्रपत्रों का उपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी निविदाएं जमा कर सकते हैं इसके लिए नया प्रपत्र खरीदना आवश्यक नहीं होगा जिला प्रशासन के अनुसार यह तृतीय लघु निविदा सूचना कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जारी की गई है पात्र भवनों का चयन निर्धारित मानकों और निविदा की शर्तों के अनुरूप किया जाएगा ताकि विदेशी मदिरा दुकान का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके इच्छुक भवन स्वामियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

शिवपुरी में तेज रफ्तार स्लीपर बस हाईवे के मीडियन में उतरी, बड़ा हादसा टला



मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग-46 (एनएच-46) पर एक स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर हाईवे के मीडियन में उतर गई मीडियन की गीली मिट्टी में बस फंस जाने से वह पलटने से बच गई जिससे बड़ा हादसा टल गया दुर्घटना में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जानकारी के अनुसार कृष्णा ट्रेवल्स की बस क्रमंक MP 31 2D 8199 इंदौर से ग्वालियर जा रही थी बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे बदरवास के सड़ बाईपास के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे के मीडियन में उतर गई हादसे के बाद बस चालक और स्टाफ

मौके से फगर हो गए जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर बदरवास थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला पुलिस ने यात्रियों को उनके गंतय तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था भी कराई हादसे में बामोरकला निवासी मोनिका जादव सहित कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस चालक शुरू से ही तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था उनका कहना है कि सफर के दौरान कई यात्रियों ने चालक से बस की रफ्तार कम करने के अनुरोध किया था लेकिन उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया।

शिवपुरी में संदिग्ध हालात में युवक का शव मिला, बुआ के घर आया था नेतराम



मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के जाखनौद गांव में बुधवार सुबह एक 25 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खरंजे पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नेतराम आदिवासी (25) निवासी देहदेह के रूप में हुई है परिजनों के अनुसार नेतराम मंगलवार को अपनी मां से जाखनौद स्थित बुआ कारी आदिवासी के घर

जाने की बात कहकर निकला था और रात में वहीं पहुंचा था बुधवार सुबह गांव की महिलाएं पानी भरने जा रही थीं तभी उन्होंने खरंजे पर नेतराम को बेसुध अवस्था में पड़ा देखा महिलाओं ने तत्काल इसकी सूचना उसकी बुआ को दी कारी आदिवासी अपने दामाद के साथ मौके पर पहुंचीं जहां उन्होंने नेतराम को मृत पाया इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई पोहरी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर संदिग्ध मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

शिवपुरी में सरपंच दंपती 20 हजार की रिश्तत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, कपिलधारा योजना का भुगतान कराने मांगी थी रकम

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले की खनियाधाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जुंगीपुर की सरपंच और उनके पति को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने 20 हजार रुपये की रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है आरोप है कि दोनों ने कपिलधारा योजना के तहत निर्मित कुएं का भुगतान जारी कराने के बदले हितग्राही से रिश्तत की मांग की थी। लोकायुक्त की टीम ने बुधवार सुबह सरपंच के आवास पर ट्रेप कारवाई करते हुए दोनों को रिश्तत की रकम के साथ पकड़ लिया जानकारी के ग्राम जुंगीपुर निवासी हितग्राही रहल सिंह यादव ने वर्ष 2025 में कपिलधारा योजना के अंतर्गत अपने खेत में कुएं का निर्माण कराया था निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भुगतान स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही थी आरोप है



कि ग्राम पंचायत की सरपंच केशवती कोली और उनके पति खेमचंद कोली ने भुगतान जारी करने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्तत की मांग की। रिश्तत की मांग से परेशान होकर रहल सिंह यादव ने 3 जुलाई 2026 को ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले का सत्यापन कराया शिकायत सही पाए जाने पर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के

लिए ट्रेप की योजना बनाई गई बुधवार सुबह करीब 10 बजे लोकायुक्त की टीम उपजेल के पीछे स्थित सरपंच के आवास पहुंची शिकायतकर्ता द्वारा तय राशि देने के दौरान टीम ने छाप मारकर सरपंच केशवती कोली और उनके पति खेमचंद कोली को 20 हजार रुपये की रिश्तत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कारवाई के बाद लोकायुक्त टीम परियादी और दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर तत्काल वहां से रवाना हो गई

कुछ समय तक उनके ठिकाने की जानकारी नहीं मिलने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और यहां तक अफवाह फैल गई कि कारवाई करने वाली टीम फर्जी थी हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि लोकायुक्त की टीम वैधानिक कारवाई पूरी करने के लिए पिछोर थाना क्षेत्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित दिनाग रेस्ट हाउस पहुंची थी जहां पंचनामा सहित अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस ट्रेप कारवाई का नेतृत्व लोकायुक्त निरीक्षक उपेंद्र डुबे और निरीक्षक अंजली शर्मा ने किया कारवाई में प्रधान आरक्षक देवेंद्र पवैया, हेमंत शर्मा, आरक्षक प्रदीप कुशवाहा, अंशु शर्मा, सुंदर सेमल, आरिफ खान, बिसंबर भटौरिया, बलबीर सहित लोकायुक्त की टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।

सरगुजा कमिश्नर का एमसीबी कलेक्ट्रेट में आकस्मिक निरीक्षण, लंबित फाइलों के त्वरित निराकरण और डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जावाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने बुधवार को एमसीबी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान

उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं, दस्तावेजों के संधारण, लंबित प्रकरणों और विभिन्न शाखाओं में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़ तथा अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार भी उपस्थित रहे। कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के

विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों और शाखाओं का निरीक्षण किया उन्होंने एआरआईएस कक्ष, आवक-जावक शाखा, निर्वानचन शाखा, वित्त शाखा और स्थापना शाखा सहित अन्य विभागों में पहुंचकर वहां संचालित कार्यों की जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यालयीन प्रक्रिया, फाइलों की स्थिति और उनके निराकरण की गति के संबंध में चर्चा की निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव और फाइलों के समय पर निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शासकीय कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखना आवश्यक है किसी

भी स्तर पर अनावश्यक रूप से फाइलों को लंबित नहीं रखा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर ने अधिकारी सुंदर जैन को समय-सीमा बैठक की कार्यवाही को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से कार्यों की निगरानी और समीक्षा अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) से संबंधित सभी दस्तावेजों और फाइलों को स्कैन कर डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए ताकि जल्दतः पड़ने पर संबंधित जानकारी आसानी से

उपलब्ध कराई जा सके। निरीक्षण के दौरान निर्वानचन, वित्त और स्थापना शाखा की फाइलों का अवलोकन करते हुए कमिश्नर ने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया का नियमित रूप से प्रतिदिन निराकरण किया जाए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यालयों में लंबित फाइलों की संख्या कम करना और नागरिकों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण की स्थिति और लंबित मामलों की भी जानकारी ली कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों से संबंधित

शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए शिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी है कि कार्यालयीन व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित हो, रिकॉर्ड सुरक्षित रहें और नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिले उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने, जिम्मेदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन करने और शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

नान्डेड-टनकपुर एक्सप्रेस 12 जुलाई से इटारसी होकर चलेगी,बीना, रानी कमलापति स्टेशनों पर भी होगा ठहराव



मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। नान्देड-टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 12 जुलाई से शुरू होगा। यह ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। इससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच सीधा रेल संपर्क मिलेगा। गाड़ी संख्या 17631 नान्देड-टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक रिविवार को रात 11:40 बजे नान्देड से रवाना होगी। यह ट्रेन पूर्णा, अकोला और खंडवा होते हुए अगले दिन दोपहर 11:55 बजे इटारसी पहुंचेगी और 12:05 बजे आगे बढ़ेगी। इसके बाद, यह रानी कमलापति में दोपहर 1:40 बजे से 1:45 बजे तक और बीना में शाम 3:55 बजे से 4:00 बजे तक रुकेगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 5:55 बजे टनकपुर पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 17632 टनकपुर-नान्देड साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9:00 बजे टनकपुर से चलेगी। यह बीना में रात 12:50 बजे से 12:53 बजे तक, रानी कमलापति में रात 2:40 बजे से 2:50 बजे तक और इटारसी में सुबह 4:10 बजे से 4:20 बजे तक ठहराव लेगी। उसी दिन शाम 4:30 बजे यह ट्रेन नान्देड पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जानकारी NTES या रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें।

रायसेन में साइबर जागरूकता पर मैराथन,सेफ क्लिक 2.0' अभियान का समापन, 2 किलोमीटर दौड़कर लोगों को किया जागरूक



मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। मध्य प्रदेश पुलिस का 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर जागरूकता अभियान बुधवार का समापन हो गया। 24 जून से चल रहे इस अभियान के तहत रायसेन जिले में भी लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने किया था, जबकि समापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक की उपस्थिति में हुआ। अभियान के समापन अवसर पर जिला पुलिस लाइन से एक साइबर जागरूकता मैराथन दौड़ आयोजित की गई। मैराथन से पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक ने पुलिसकर्मियों और ताड़कवांडो खिलाड़ियों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान एसडीओपी प्रतिभा शर्मा और आरआई कविता डामोर भी मौजूद थीं। एएसपी दीपक नायक ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ में शामिल हुए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और ताड़कवांडो खिलाड़ी साइबर जागरूकता संबंधी संदेश लिखे पोस्टर लेकर मैराथन में दौड़े। दौड़ का समापन सागर रोड पर हुआ। अभियान के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रदान की गईं। पुलिस ने अपील की कि वे अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य गोपनीय दस्तावेज किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की सलाह दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिलेभर में आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को डिजिटल दुनिया में सतर्क और सुरक्षित बनाना था, जिसे जिलेभर में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया।

सीहोर में भोपाल के तीन चोर गिरफ्तार,सूने घरों को बनाते थे निशाना, 1.30 लाख रुपए के जेवर और मोबाइल बरामद



मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सूने मकान में चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में भोपाल जिले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन सहित करीब 1.30 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, 7 मार्च 2026 को सीहोर निवासी सुरेखा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर उनके सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नगर पुलिस अधीक्षक अभिनंदना शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रविन्द्र यादव के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना उर्फ रोहित शिल्पकार निवासी वार्ड नंबर 13, सिलावट मोहल्ला, बैरसिया, भारत उर्फ भरत काला निवासी पलासी करोंद, जिला भोपाल और करन शाक्य निवासी वार्ड नंबर 17, शांतिकुंज, बैरसिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पृष्ठछाछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया।

1.30 लाख रुपए का सामान बरामद: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया है। इसमें करीब 5 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र पेंडेंट और 8 सोने के पारे, जिनकी कीमत करीब 75 हजार रुपए है।

मैराथन से दिया साइबर जागरूकता का संदेश

साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर दे सूचना; 5 किमी तक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी दौड़े

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम में साइबर जागरूकता अभियान 'सेफ क्लिक 2.0' के तहत मंगलवार सुबह पुलिस विभाग ने साइबर सुरक्षा का संदेश देने के लिए साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया। करीब पांच किलोमीटर लंबी इस मैराथन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दौड़ लगाई। मैराथन के माध्यम से प्रतिभागियों ने लोगों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने का संदेश दिया। मैराथन का शुभारंभ पोली ग्राउंड से हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राकेश पट्टे ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। मैराथन पोली ग्राउंड से शुरू होकर छत्री पुल, आरोग्यम हॉस्पिटल, लोकेंद्र टॉकीज चौराहा, दो बत्ती चौराहा और महाराजा सज्जन सिंह चौराहे से होते हुए पुनः पोली ग्राउंड पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। मैराथन में पुलिस अधिकारियों और



कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों तथा वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

तीन वर्गों में हुई: मैराथन तीन वर्गों में हुई। महिला वर्ग में कॉन्स्टेबल आरती चौधरी ने प्रथम स्थान, स्वाति शर्मा ने

द्वितीय स्थान एवं निकिता वीरवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में कॉन्स्टेबल दीपलाल नर्गिस ने प्रथम स्थान, आरक्षक सूर्यपाल सिंह चंद्रावत ने द्वितीय स्थान एवं आरक्षक सुनील गरवड़ा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में

सीहोर में झुके बिजली के खंभे,झूलते 11 केवी तार बने जानलेवा, किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की क्षतिग्रस्त लापरवाही को लेकर किसानों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बिलकिसगंज-चंदेरी मुख्य मार्ग सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी हाइड्रेशन लाइन के खंभे खतरनाक तरीके से झुक गए हैं और बिजली के तार जमीन के बेहद करीब झूल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

11 केवी लाइन बनी खतरा, पहले भी हो चुके हैं हादसे: ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग की अनदेखी के कारण क्षेत्र में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले वर्ष करंट लगने से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं, इस वर्ष किसान सतीश मेवाड़ा भी करंट की चपेट में आ गए। उनका इलाज वर्तमान में भोपाल के एक अस्पताल में चल रहा है। इन घटनाओं के बाद



भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।

किसानों ने खोला मोर्चा, दो बार सौंपा ज्ञापन: किसान एसएस मेवाड़ा के नेतृत्व में दर्जनों गांवों के किसानों और ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर दो बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं,

लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत मंडल के अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं।

तत्काल सुधार की मांग, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन: ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग को अंतिम चेतावनी देते

हुए कहा है कि बिलकिसगंज-चंदेरी मार्ग सहित पूरे सीहोर जिले में झुके बिजली के खंभों और झूलते तारों को तत्काल बदला जाए। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली विभाग की होगी।

बिजली विभाग का पक्ष: इस मामले में बिजली विभाग का कहना है कि बिजली लाइनों और खंभों के रखरखाव का कार्य समय-समय पर किया जाता है। विभाग का दावा है कि आवश्यकतानुसार मरम्मत और सुधार की प्रक्रिया जारी रहती है।

सीहोर में झूलते बिजली के तार और झुके खंभे ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। किसानों की चेतावनी के बाद अब सभी की नजर प्रशासन और बिजली विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है।

चाय पीने गए दोस्तों की कार पिकअप से टकराई, मंदसौर में युवक के चेहरे पर 20 टांके आए, आंख और मुंह में लगी



मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर शहर के सर्किट हाउस के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे एक सड़क हादसे में कार सवार दो दोस्त घायल हो गए। उनकी कार आगे चल रही पिकअप से टकरा गई। सूचना मिलने पर डायल-112 ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय हुड्डा आई-20 कार में उज्जैन निवासी संजय साहू (25) और मंदसौर के अभिनंदन नगर निवासी ओम सोनी (22) सवार थे। दोनों दोस्त नयाखेड़ा से चाय पीकर मंदसौर लौट रहे थे। सर्किट हाउस के पास अचानक पिकअप के ब्रेक लगाने से कार अनियंत्रित होकर पीछे से उसमें जा घुसी। इस टक्कर में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ओम सोनी को चेहरे और हाथ में चोटें आई हैं, जबकि संजय साहू के चेहरे, सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगी हैं। चिकित्सकों ने बताया कि संजय के चेहरे पर करीब 20 टांके लगाए गए हैं।

खरगोन में तेज बारिश, स्कूल परिसर में भरा पानी,जिले में औसत 9.4 इंच दर्ज, अगले 3 दिन और बारिश के आसार

मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन जिले में बुधवार सुबह से मौसम ने अचानक कवट ले ली। सुबह करीब 9:30 बजे शुरू हुई तेज और रुक-रुककर होने वाली बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में अब तक औसतन 240 मिमी (करीब 9.4 इंच) बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश का असर स्कूलों, यातायात और किसानों की खेती पर साफ दिखाई दे रहा है।

स्कूल परिसर में भरा पानी: तेज बारिश के कारण कुकड़ोल स्थित एक स्कूल परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। स्कूल पहुंचने वाली छात्राओं को पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई अभिभावक भी बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने



के लिए साध आएं। बारिश के चलते सुबह के समय आवागमन भी प्रभावित रहा।

लगातार बारिश से खेतों में रुका कृषि कार्य: पिछले दो-तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जिले में कृषि कार्य भी प्रभावित हो गया है। किसान अरविंद जायसवाल ने बताया कि गर्मी की कपास की फसल में तेजी

से खरपतवार बढ़ रही है। लगातार गीली मिट्टी के कारण खेतों में कोलप जैसे कृषि औजारों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे फसल की देखरेख में परेशानी आ रही है।

तीन दिन और होगी तेज बारिश: मौसम विभाग ने खरगोन जिले के लिए अगले तीन दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है।

बुरहानपुर में बारिश बनी आफत,कई वार्ड जलमग्न, पिछले साल से दोगुनी से ज्यादा बारिश दर्ज

मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरसात से पहले नालों की सफाई और जलभराव रोकने के दावों के बावजूद शहर के कई वार्डों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। लगातार बारिश से आमजन, वाहन चालकों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोहार मंडी से बुधवारा तक जलभराव: बारिश के बाद लोहार मंडी, हरीरपुरा, मोमिनपुरा, सिंधीपुरा और बुधवारा समेत कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। नालियों की गंदगी बारिश के पानी के साथ सड़कों पर फैलने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। वहीं, शहर की कई सड़कें पहले से ही



खराब हैं। ऐसे में गड्ढों में पानी भर जाने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़

गया है। **जिले में पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बारिश:** जिले में 1

जून से अब तक औसतन 287.7 मिमी (करीब 11.3 इंच) बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 131.8 मिमी बारिश की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 823.6 मिमी मानी जाती है, जिससे स्पष्ट है कि मानसून की शुरुआत में ही अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

नेपानगर में सबसे ज्यादा बारिश, खकनार में कम वर्षा: कलेक्टर भू-संसाधन प्रबंधन के अनुसार, बुरहानपुर तहसील में अब तक 318.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 129.4 मिमी वर्षा हुई थी। नेपानगर में सबसे अधिक 419.0 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले साल की 132.0 मिमी वर्षा से काफी ज्यादा है। वहीं धूलकोट में 301.9 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि पिछले वर्ष यहां 116.8

मिमी बारिश हुई थी। दूसरी ओर खकनार में अब तक 111.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुई 149.0 मिमी बारिश से कम है।

जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल: लगातार हो रही बारिश के बीच शहर में जलभराव की स्थिति ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालों की प्रभावी सफाई और सड़कों की मरम्मत होती तो जलभराव और यातायात संबंधी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता था। बुरहानपुर में इस बार मानसून की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई है, लेकिन जल निकासी व्यवस्था की कमजोर तैयारियों के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यदि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो प्रशासन के सामने जलभराव और यातायात प्रबंधन की चुनौती और बड़ी हो सकती है।



सौरव गांगुली: वो कप्तान, जिन्होंने टीम इंडिया को सिखाई ‘दादागिरी’

नई दिल्ली, एजेसी। सौरव गांगुली देश के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में शुमार है। ‘दादा’ के नाम से मशहूर गांगुली ने भारतीय टीम में आक्रामक सोच और युवा खिलाड़ियों को अवसर देने की परंपरा को मजबूत किया। बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज गांगुली ने भारत को विदेशों में कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। संन्यास के बाद दादा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का अध्यक्ष पद भी संभाला। 8 जुलाई 1971 को कोलकाता के समृद्ध परिवार में जन्मे सौरव के पिता चंडीदास गांगुली एक शानदार क्लब क्रिकेटर थे, उनके भाई भी इस खेल के शौकीन थे। ऐसे में घर पर हमेशा क्रिकेट की बातें होती रहतीं। परिवार के अधिकतर सदस्य बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। ऐसे में सौरव को भी उल्टे हाथ से बल्लेबाजी करने की आदत पड़ गई। उनके बड़े भाई स्नेहाशीष बंगाल की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन सौरव ने क्रिकेट के बजाय फुटबॉल को तरजीह दी। 13 साल की उम्र में सौरव गांगुली को स्मर क्रिकेट कैप में भेजा गया, जहां इस खेल को लेकर उनकी रुचि जगी। बंगाल और ओडिशा के बीच एक फ्रेंडली अंडर-15 मैच में बंगाल की टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी। सौरव को मौका दिया गया और उन्होंने सेंचुरी लगा दी। ये शतक उनके करियर में टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। परिवार ने घर के पास 2 कंक्र्रीट की पिचें बनवाईं, जिसमें सौरव के साथ स्नेहाशीष प्रैक्टिस करते थे। दोनों के लिए एक कोच भी रखा गया। साथ ही घर में जिम की व्यवस्था भी की गई। सौरव गांगुली ने साल 1989 में रणजी डेब्यू किया। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद आखिरकार गांगुली को साल 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू का मौका मिल गया, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 3 रन निकले। इसके बाद गांगुली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। करीब चार साल बाद साल 1996 में उन्हें टेस्ट में भी पदार्पण का मौका मिला, जिसमें

इंग्लैंड के खिलाफ पहली ही पारी में 20 चौकों के साथ 131 रन बनाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी। अपने दूसरे टेस्ट में गांगुली ने 136 और 48 रन की पारी खेली। इसके बाद ‘प्रिंस ऑफ कोलकाता’ ने धीरे-धीरे भारतीय टीम में अपना स्थान मजबूत कर लिया। सौरव ‘ऑफ-साइड’ में इतना शानदार स्ट्रोक लगाते थे कि उन्हें ‘गॉड ऑफ ऑफ-साइड’ कहा जाने लगा। गांगुली एक भरोसेमंद जोड़ीदार भी थे। 26 मई 1999 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप मैच में गांगुली ने राहुल द्रविड के साथ दूसरे विकेट के लिए 318 रन की साझेदारी की। तेंदुलकर के साथ उन्होंने 176 पारियों में 47.55 की औसत से कुल 8,227 रन बनाए। 26 मई 1999 को श्रीलंका के खिलाफ 158 गेंदों में 7 छक्कों और 17 चौकों के साथ 183 रन की पारी खेली। मैच फिक्सिंग विवाद के चलते भारतीय क्रिकेट मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इस बीच सचिन तेंदुलकर ने भी कप्तानी छोड़ दी थी। ऐसे में गांगुली को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके नेतृत्व ने टीम में नया जोश जगा दिया। गांगुली की कप्तानी में भारत ने आक्रामक रवैये के साथ खेलना सीखा। ये वो दौर था, जब भारतीय खिलाड़ी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब दे रहे थे। गांगुली की कप्तानी में भारत ‘आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002’ का संयुक्त विजेता रहा, जबकि ‘वनडे वर्ल्ड कप 2003’ के फाइनल में जगह बनाई। दादा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाकर इन दिग्गज टीमों को अपना दमखम दिखाया। सौरव गांगुली ने युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान और महेंद्र सिंह धोनी जैसे युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया। भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए गांगुली को साल 1997 में ‘अर्जुन अवॉर्ड’, जबकि साल 2004 में ‘पद्म श्री’ से नवाजा गया।

अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में रेफरी के फैसलों से निराश मिश्र ने फीफा से की शिकायत



बॉडी से संपर्क किया है। मिश्र के खिलाड़ियों के गुस्से और निराशा का कारण उनके खिलाफ गए कुछ फैसले हैं, जिनमें वीएआर समीक्षा के बाद एक गोल को नामंजूर करना और अर्जेंटीना के विजयी गोल की तैयारी में एक पेनल्टी अपील का समीक्षा नहीं किया जाना शामिल है। स्पैनिश पब्लिकेशन डियारियो एएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिश्र फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, हनी अबो रिडा ने फ्रेंच रेफरी फ्रैंकोइस लेटैक्सियर और उनकी रेफरी टीम के खिलाफ फीफा में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शिकायत में उन विवादों में घिरे फैसलों की जांच की मांग की गई है, जिन्हें मिश्र ने फैंरो के खिलाफ बताया है। फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर यह भी अनुरोध किया है कि फ्रेंच रेफरी टीम को बाकी टूर्नामेंट से हटा दिया जाए, क्योंकि वह इसे बहुत बड़ी गलती मानता है।इससे पहले, मिश्र के कोच हसन ने भी कई फैसलों पर निराशा जताई थी। उन्होंने यह भी कहा कि नतीजे पर पिच पर जो हुआ उससे कहीं ज्यादा वजहों का असर पड़ा, यहां तक ​​​​?कि उन्होंने यह भी इशारा किया कि मेसी और अर्जेंटीना टूर्नामेंट में बने रहना चाहते थे।हसन ने कहा, ‘हम मौजूदा चैंपियन से बेहतर दिखे-हर चीज में बेहतर-लेकिन नतीजे पर पिच के अंदर की वजहों और पिच के बाहर की बाहरी वजहों का असर पड़ा। ‘उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘शायद वे वर्ल्ड चैंपियन को टूर्नामेंट में बनाए रखना चाहते थे। शायद वे चाहते थे कि मेसी लौट में बने रहें। फुटबॉल में, कभी-कभी बाहरी वजहें होती हैं जो तकनीकी बातों से आगे निकल जाती हैं।

रोनाल्डो का विश्वकप जीतने का सपना अधूरा रह गया

स्पेन ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में 1-0 से हराया

डलास, एजेसी। स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 1-0 से मिली हार के साथ ही पुर्तगाल की टीम फीफा विश्वकप फुटबॉल से बाहर हो गयी। इसी के साथ ही पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्वकप जीतने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। इसका कारण है कि रोनाल्डो की उम्र 41 के करीब है और उन्होंने कहा था कि अगले विश्वकप में उनके खेलने की कोई संभावनाएं नहीं है। स्पेन के खिलाफ हार के बाद रोनाल्डो ने भी पुष्टि की है कि यह उनके करियर का अंतिम विश्व कप

था हालांकि उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का अभी उनका कोई इरादा नहीं है। स्पेन के खिलाफ मुकाबले में तय समय तक दोनों ही टीमें बराबरी पर थीं। वहीं दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में स्पेन के खिलाफ डी.मि को लेकर मेरिनो ने एक गोल कर पुर्तगाल को बाहर कर दिया। हार के बाद रोनाल्डो हताश दिखे। उन्होंने माना है कि इस तरह हार के साथ ही अपने अंतिम विश्व



दुबई , एजेसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा जारी टी20 के बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाजों ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ईशान किशन टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले

स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के दूसरे मैच में नाबाद 76 रनों की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज जैकब बेथेल को रैंकिंग में बढ़ा फायदा हुआ है। बेथेल 7 स्थान ऊपर चढ़ते हुए आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श नौवें, जबकि दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस दसवें स्थान पर हैं। टी20 गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान पहले, पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे, इंग्लैंड के आदिल रशीद 1 स्थान ऊपर चढ़ते हुए तीसरे, और ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा 1 स्थान ऊपर चढ़ते हुए चौथे स्थान पर हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती को 2 स्थान का घाटा हुआ है, वह पांचवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस और दक्षिण अफ्रीका के कार्बिन बोश क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं। दोनों को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। जसप्रीत बुमराह को दो स्थान का घाटा हुआ है, वह आठवें स्थान पर हैं। श्रीलंका के पाथुम निरसांका नौवें और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान दसवें स्थान पर हैं।

4 मुकाबलों के बाद आप बुरी टीम नहीं बन जाते

तीसरे टी20 में करारी हार के बाद बोले कोच गंभीर

नॉटिंघम , एजेसी। भारतीय टीम को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। ट्वेंट ट्वेंटी क्रिकेट के मैदान पर भारत का बल्लेबाजी क्रम तारा के पतों की तरह बिखर गया और पूरी टीम महज 76 रन बनाकर सिमट गई। हालांकि, हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम का बचाव किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए गंभीर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आप चार मैच के बाद बुरी टीम नहीं बन जाते। कभी-कभार आपकी विरोधी टीम अच्छा खेलती है, कभी आप परिस्थितियों को ठीक तरह से भांप नहीं पाते हैं। गेम को समझना भी काफी जरूरी है, जो हम आयरलैंड सीरीज से नहीं कर सके हैं।’ हेड कोच ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड क्या करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको खुद को बेहतर करने पर ध्यान देना होगा।



एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग: तीसरे दिन मीतेई, आदित्य और सिकंदर का शानदार प्रदर्शन

जकार्ता, एजेसी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जारी एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन अंडर-19 कैटेगरी में अंबेडकर मीतेई (50 किग्रा) ने पुरुषों के वर्ग में दमदार जीत हासिल की। मीतेई ने चीनी ताइपे के ची-यू शियाओ के खिलाफ पहले ही राउंड में रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट (आरएससी) के जरिए शानदार जीत दर्ज की। लड़कों के वर्ग में, आदित्य (55 किग्रा) ने किर्गिस्तान के डेनियल ताशतानबेकोव के खिलाफ 5:0 से

आसान जीत हासिल की, जबकि सिकंदर (60 किग्रा) ने कोरिया के ताईमिन यांग के विरुद्ध मुकाबला 5:0 से जीता। भारत की जीत का सिलसिला आगे बढ़ते हुए, देवेंद्र चौधरी (75 किग्रा) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और चीनी ताइपे के सुंग-लिन त्साई को दूसरे राउंड में आरएससी के जरिए हराया। प्रशांत (70 किग्रा) ने कजाकिस्तान के बिबारिस आशिरवे के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया। हदला राउंड 1:4 से हारने के बाद, उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा राउंड 3:2 से अपने नाम किया, लेकिन आखिरी

राउंड में वे 3:2 के मामूली अंतर से हार गए। अंडर-19 कैटेगरी में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन देश के यूथ बॉक्सिंग प्रोग्राम की गहराई और गुणवत्ता को दिखाता है, जिसमें कई बॉक्सर शुरुआती राउंड में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जकार्ता में 5 से 16 जुलाई तक जारी एशियन अंडर-19 और अंडर-23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत के युवा टैलेंट के लिए एक अहम मंच बनी हुई है, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलता है। ये मुक़ाबला भविष्य के बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हो रहे हैं।



अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि देने में अनावश्यक विलंब न हो : कमिश्नर

जाति प्रमाण पत्र के अभाव में जांच एवं विवेचना में देरी न हो सभी प्रकरणों में तामीली प्राथमिकता से कराई जाए

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शासन के निर्देश अनुसार रहत राशि देने में विलस भी प्रकर का विलंब न हो यदि राशि का आवंटन नहीं है तो प्राथमिकता से शासन स्तर से राशि आवंटित कराकर पीड़ित व्यक्तियों को रहत राशि देना सुनिश्चित किया जाए उक्त निर्देश रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के अंतर्गत गठित संभाग स्तरीय सतर्कता सलाहकर एवं अनुव्रण समिति की बैठक में दिए बैठक में पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस, मैहर कलेक्टर मती विदिशा मुखर्जी मऊअंज कलेक्टर संजय कुमार जैन, सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा,



सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल, रीवा के पुलिस अधीक्षक गुरकरन सिंह एवं संभाग के अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकगण तथा सभी जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे कमिश्नर ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे सभी थाना प्रभारियों के लिए निर्देश जारी करें कि

एसडीएम से जाति प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर जाति प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी प्रकरण की जांच या विवेचना लंबित न रहे और न ही विवेचना में किसी भी प्रकरण की देरी हो कमिश्नर ने अभियोजन स्वीकृति एवं न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की समीक्षा की,

उन्होंने अपराधिक व्यक्तियों को मिलने वाली कम सजा पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए की सभी प्रकरणों में बरीकी से जांच पड़ताल कर दोषी व्यक्तियों के विरुध ठोस प्रकरण बनाए जाएं। कमिश्नर ने सभी प्रकरणों में तामीली की गति बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि तामीली शत

प्रतिशत की जाए। साथ ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने में शीघ्रता की जाए कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी प्रकरण गुणवत्ता पूर्ण बनाए जाएं, समय पर पीड़ित व्यक्ति एवं गवाह को रहत राशि मिल जाए उन्होंने सभी जिला अभियोजन अधिकारियों से कहा कि वह अतिरिक्त मेहनत करके दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने एवं पीड़ित व्यक्तियों को रहत देना सुनिश्चित करें, कमिश्नर ने कहा कि सभी जिला अभियोजन अधिकारी अपने काम में कसावट लाएं कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए शासन के निर्देशानुसार अन्य जिलों की प्रेषित प्रकरण के भुगतान आदेश की प्रति अन्य जिलों से प्राप्त होती है भुगतान की जानकारी नियमित रूप से प्रेषित की जाए कमिश्नर ने अत्याचार से पीड़ित एवं आश्रित व्यक्तियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ता, भरण पोषण,

आहार एवं पीड़ितों को रोजगार प्रदान करने आदि के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए कमिश्नर ने कहा कि जिन थाना क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित अधिक संख्या में प्रकरण दर्ज होते हैं उन थाना क्षेत्र के लोगों में आपस में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकर के सद्भावना के कार्यक्रम आयोजन किए जाएं साथ ही प्रकरणों में सजा का प्रतिशत बढ़ाने हेतु एवं पीड़ितों तथा गवाहों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला अभियोजन अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी परस्पर समन्वय स्थापित करें कमिश्नर ने निर्देश दिए की रीवा संभाग के सभी जिलों में जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाए।

डॉ. सीएल रावत बने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत डॉ. सीएल रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की सहमति से यह नियुक्ति अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह तैकाम द्वारा की गई है। डॉ. रावत की नियुक्ति भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता की अनुमंसा पर हुई है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉ. सीएल रावत ने अपनी नियुक्ति पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित संगठन के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे तथा संगठन की मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य करेंगे डॉ. रावत की नियुक्ति के बाद भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर



निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं बधाई देने वालों में भाजपा जिला पदाधिकारी, महिला मोर्चा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, नगर निगम पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे नेताओं ने कहा कि डॉ. सीएल रावत के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति मोर्चा को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन की गतिविधियां और अधिक प्रभावी होंगी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि डॉ. रावत समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं ने मिठवाई बांटकर खुशी भी जाहिर की और नए जिलाध्यक्ष के सफल कार्यकाल की कामना की।

जुलाई-अगस्त में एसकेएम करेगा बड़ा आंदोलन, किसान संघर्ष समिति ने बनाई रणनीति



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अमेरिकी-भारत व्यापार समझौते (ट्रेड डील) का विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने जुलाई और अगस्त माह में देशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की है किसान संघर्ष समिति ने भी इन आंदोलनों में व्यापक भागीदारी करने का निर्णय लिया है किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट शिव सिंह ने बताया कि ऋग्शज पार्क रीवा में समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी

अध्यक्षता जिला अध्यक्ष फौजी यदुवंश प्रताप सिंह ने की। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों और आगामी आंदोलनों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखु, प्रदेश सचिव संतकुमार पटेल, जिला अध्यक्ष मऊअंज अजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष लोकनाथ पटेल, सेमरिया अध्यक्ष फौजी चक्रधर सिंह, जिला सचिव अनिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे बैठक में एसकेएम के आह्वान पर 22 जुलाई को देशभर में एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) विरोधी किसान संकल्प दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसके

अलावा 28 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किसान सम्मेलन तथा 29 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई किसान नेताओं ने बताया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के हस्ताक्षर होने के अगले दिन बड़े आंदोलन की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 10 अगस्त को किसानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की गई है इस आंदोलन में खद और डीजल की कमी, बढ़ती महंगाई, एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी, भूमि अधिग्रहण पर रोक सहित अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। किसान संघर्ष समिति ने दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में किसानों को शामिल करने का आह्वान किया है बैठक में नेताओं ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा उन्होंने सभी किसानों से आगामी आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।

पॉक्सो एक्ट के मामले में सभी पुलिस अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें : कमिश्नर साइबर धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह बुधवार को कमिश्नर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में रीवा संभाग के सभी जिलों की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की कमिश्नर ने बैठक में उपस्थित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वह पॉक्सो एक्ट के मामले में पूरी संवेदनशीलता से कार्य

करें, पॉक्सो एक्ट में दर्ज प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और हर प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए साइबर प्रॉड एवं साइबर धोखाधड़ी के संबंध में हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह साइबर धोखाधड़ी के बारे में आम

जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करें और लोगों को साइबर प्रॉड से बचने के तरीके के बारे में बताएं बताया गया कि अब तक रीवा में 91 साइबर धोखाधड़ी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किया जा चुके हैं, इसी क्रम में सतना में 66, सीधी में 247 मैहर में 68, मऊअंज में 65 जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं बैठक में बताया गया कि रीवा संभाग के सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में ड्रा प्रि जोन बनाया गया है इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे को ड्रा जोन प्रि बनाने की कार्यवाही की गई है यह सुनिश्चित किया गया है कि

शैक्षणिक संस्थाओं के 500 मीटर के दायरे में शराब सिगरेट या गुटखा पाउच की कोई भी दुकान संचालित न होने पाए कमिश्नर ने राहवीर योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को इस योजना से अवगत कराया जाए उन्होंने बताया कि राहवीर योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीक के अस्पताल पहुंचाता है तो उसे शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है कमिश्नर ने राहवीर योजना अंतर्गत सभी जिलों में बने कम प्रकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए और अधिक जागरूकता के कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए।

पुनर्वास और जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने रोका पैदल मार्च



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और जलभराव की समस्या को लेकर मंगलवार को न्याय मंच के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी स्वामी विवेकानंद पार्क से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए घेराव करने जा रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संभागीय आयुक्त के नाम संबोधित ज्ञापन सीएसपी को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग

की प्रदर्शन का नेतृत्व न्याय मंच के संभागीय संयोजक अभय वर्मा और जिलाध्यक्ष राहुल वर्मा ने किया। इस दौरान समाजसेवी अविराज, अभिषेक सिंह, छोटेलाल रजक, अतुल पांडेय, आशीष द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे ज्ञापन में बताया गया कि रीवा शहर की विभिन्न बस्तियों में लंबे समय से निवास कर रहे कई परिवारों को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हटाया गया है। विस्थापन के बाद इन परिवारों के सामने आवास, रोजगार और बच्चों की शिक्षा जैसी समस्याएं

खड़ी हो गई हैं। न्याय मंच ने मांग की है कि प्रभावित परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए प्रदर्शनकारियों ने शहर में बढ़ती जलभराव की समस्या को भी प्रमुख मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि हल्की बारिश में ही कई मोहल्लों और कॉलोनियों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना

करना पड़ता है। नालियों की खराब व्यवस्था के कारण बारिश का पानी सड़कों और घरों तक पहुंच रहा है समाजसेवी अविराज ने कहा कि बिना उचित पुनर्वास के परिवारों को विस्थापित करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित लोगों को सम्मानजनक पुनर्वास और शहर में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की ज्ञापन सौंपने के दौरान अनंत मिश्रा, सतेंद्र वर्मा, अतुल पांडे, अतुल त्रिपाठी, शिव यादव, शिवा यादव सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उपस्थित रहे।



बारिश में बदहाल हुआ रीवा-मझियार मार्ग, 11 किमी सड़क पर गड्ढों से बड़ी लोगों की परेशानी



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा से मझियार तक करीब 11 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बारिश के बाद पूरी तरह जर्जर हो गया है जगह-जगह बने बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों, विद्यार्थियों किसानों और मरीजों को उठनी पड़ रही है ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है यह मार्ग आसपास के कई गांवों को

रीवा शहर से जोड़ता है जिससे प्रतिदिन सैकड़ों लोग नौकरी, व्यापार, शिक्षा और उपचार के लिए आवागमन करते हैं। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क उखड़ चुकी है बारिश के बाद जलभराव से गड्ढों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन

अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला उनका कहना है कि हर वर्ष बारिश से पहले मरम्मत के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जाती है और कुछ ही दिनों में सड़क फिर से खराब हो जाती है स्थानीय निवासी गुर्मुखि पटेल ने बताया कि गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चलाना बेहद जोखिम भरा हो गया है और कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। वहीं सीमा साकेत ने कहा कि बरसात के दौरान बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत गड्ढों को भरने तथा जल निकासी की सुविचित व्यवस्था कराने की मांग की है ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके।

राशि गबन के मामलों में पूर्व सरपंच, पूर्व सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ जेल वारंट जारी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में पंचायती गज व्यवस्था के तहत विकास कार्यों की राशि में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अखिरार किया है विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मेहाब सिंह गुर्जर द्वारा भ्रष्टाचार और शासकीय राशि के गबन के अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक पूर्व सरपंच, एक पूर्व सचिव और एक ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ गिरफ्तारी और जेल भेजने संबंधी वारंट जारी किए हैं। यह कड़ु कदम मध्य प्रदेश पंचायतव्यवस्था एवं ग्रामसंरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के तहत उठया गया है सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी वारंट के अनुसार जनपद पंचायत त्योथर की ग्राम पंचायत फरहदी में खेत तालाब निर्माण और मेंढ़ बंधान निर्माण कार्यों में कुल 1,00,237 रुपये की राशि का गबन किया गया था। इस वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव राजबहोर यादव और ग्राम रोजगार सहायक नारायण प्रसाद मिश्रा को जिम्मेदार पाया गया। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच कई बार लिखित नोटिस जारी कर वसूली राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। बार-बार सूचना पत्र दिए जाने के बावजूद दोनों आरोपियों ने राशि जमा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही पंचायत का रिकॉर्ड सौंपा। इस पर कड़ु संज्ञान लेते हुए न्यायालय विहित प्राधिकारी ने दोनों के खिलाफ धारा 92(2) के तहत वारंट जारी कर दिया है। सीईओ जिला पंचायत ने जनपद पंचायत त्योथर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे स्वयं चाकचाट थाने में उपस्थित होकर इस वारंट की तामीली करावें और आरोपियों को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल रीवा की सुपुर्दगी में भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।